वर्ष 2 अंक 11 नवंबर 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

पश्चिम बंगाल के बैंक कर्मचारियों का आह्वान

ए.आई.बी.ई.ए. नेतृत्व की कर्मचारी विरोधी भूमिका के खिलाफ संघर्ष करो

28 सितम्बर 1980 को कलकत्ता के त्यागराज हाल में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से एकत्रित बैंक कर्मचारियों ने नरेशपाल (उपप्रधान बी. पी. बी. ई. ए.), नन्दी (ग्रिण्डलेज बैंक), शांतिवर्धन (यूनियन बैंक), सुधीर चौधरी (यूनाइटिड कामर्शियल बैंक) और कल्याण सेन गुप्ता (बैंक आफ बड़ौदा) की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया. सम्मेलन में ए. आई. बी. इ. ए. के नेताओं की बैंक-मलिकान के साथ सांठ-सांठ की नीति और वेतन, अन्य आर्थिक हितों, काम-बाढ़, नौकरी सुरक्षा आदि मामलों में कर्मचारियों के हितों के साथ उनकी गद्दारी और कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन एकबद्धता को तोड़ने की उनकी फूटपरस्त गतिविधियों पर गहरा रोष प्रकट किया गया.

इस सम्मेलन में 34 बैंकों के 25,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के 793 डेलीगेटों तथा 380 आब्जर्वरों ने भाग लिया और 30 से अधिक डेलीगेटों ने बहस में भाग लिया.

प्रसंगवश, पश्चिम बंगाल में कमर्शियल बैंक दफ्तरों में लगभग 38,000 तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया में 12,000 कर्मचारी काम करते हैं इनमें से बी पी बी इ ए से सम्बन्धितों की संख्या 34,000 के करीब हैं.

कर्मचारियों के आधारभूत हितों को बलि चढ़ा देने और बैंकरों तथा सरकारी सत्ता में बैठे अपने आकाओं के आदेशों के सामने समर्पन करने के अलावा ए. आई. बी. इ. ए. के नेता और इसकी विभिन्न राज्यस्तर की यूनिटें विरोध की हर आवाज को दबाने के लिये यूनियनों को निष्कासन/एफिलियेशन खत्म करने के हथकंडे अपना रहे हैं और जो प्राथमिक यूनिटें उनकी लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनमें तोड़फोड़ करने के लिए समानान्तर संस्थाओं की स्थापना को संरक्षण दे रहे हैं.

ए. आई. बी. इ. ए. की पश्चिम बंगाल की यूनिट बी. पी. बी. इ. ए. के जनरल सेक्रेट्री ने वर्किंग कमेटी या जनरल काउंसिल के फैसले के बिना, हाल ही में 4 पदाधिकारियों (वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो ए. आई बी. इ. ए. के संस्थापकों में से एक हैं, दो ज्वाइंट सेक्रेट्रीज, सहायक कोषाध्यक्ष) को तथा 16 यूनियनों के अध्यक्षों एवं सेक्रेट्रीज को हटाने—जिसका मतलब निष्काषन है—का एलान कर दिया है, इस आधार पर कि ये लोग इस सम्मेलन के आयोजक हैं.

इन परिस्थितियों में, सम्मेलन में तालियों की जबर्दस्त गड़गड़ाहट के बीच सर्वसम्मति से एक **घोषणा** स्वीकार की गई, जिसमें बैंक कर्मचारियों का ए. आई. बी. इ. ए. और इसके राज्य यूनिट से अलग होने का आह्वान किया गया. एक 28 सदस्यीय तैयारी कमेटी चुनी गई. नरेश पाल को तैयारी कमेटी का संयोजक चुना गया. इस कमेटी को तीन महीनों में या इससे पहले सम्मेलन बुलाकर एक नया राज्य स्तर का संगठन स्थापित करने और **घोषणा** के पैरा 17 में रेखांकित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को सही तरीके से प्रतिबिम्बित करने वाले बैंक कर्मचारियों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहल कदमी करने का कार्यभार सौंपा गया. यह घोषणा यहां प्रकाशित की जा रही है.

18 नवंबर से गोदी व बंदरगाह के मजदूरों की अखिल भारतीय लगातार हड़ताल

घोषणा

भूमिका

1. दिसम्बर 1945, में "आल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन" (ए.आई.बी.ई.ए.) का गठन उन परिस्थितियों में किया गया था, जब कि बैंक कर्मचारी नौकरी-सुरक्षा निश्चित वेतन-मानों, ट्रेड-यूनियन तथा जनवादी अधिकारों आदि के अभाव में रात-दिन अपमानित व प्रताड़ित होकर दमन की चक्की में पिस रहे थे.

2. बैंक कर्मचारियों को बैंकरों तथा सरकार के हमलों से बचाने के लिए, उनकी आर्थिक-स्थिति में सुधार के लिए, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ट्रेड-यूनियन तथा अन्य जनवादी अधिकारों आदि को हासिल करने के लिए—पूरे देशके बैंक कर्मचारियों को एक सूत्र में एकता-बद्ध करना ए. आई. बी. इ. ए. का उद्देश्य था.

3. इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ट्रेड यूनियन में जनवादी कार्य-प्रणाली के मजबूत आधार पर इस संगठन को खड़ा किया गया था.

4. वर्ग-संबंधों की भाषा में कहें तो चूंकि बैंक कर्मचारी मजदूर वर्ग का अंग है इसलिए पूरे मजदूर-वर्ग के साथ पूर्ण-सहयोग और घनिष्ठ एकता बनाकर चलने के लिए, अपने आंदोलनों और संघर्षों के लिए मजदूर वर्ग के ही मार्ग-दर्शक सिद्धान्त अपनाये गये थे.

5. उपरोक्त उद्देश्यों के साथ ए. आई. बी. इ. ए. की स्थापना के आरंभिक वर्षों में देश के विभिन्न भागों में बहुत से बैंकों के कर्मचारियों को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिला और वे बड़े उत्साह के साथ संगठन को बड़े पैमाने पर मजबूती से खड़ा करने के लिए आगे बढ़े. ट्रेड यूनियन आंदोलन और संघर्षों के इतिहास में ए. आई. बी. ए. इ. ने मूल्यवान छाप छोड़ी. इससे विरोधी-शक्तियों बैंकरों और सरकारी सत्ता में बैठे उनके सरपरस्तों को जबर्दस्त आघात लगा.

6. बैंक कर्मचारियों की जुझारू अग्रगति को रोकने के लिए सरकार ने उनके वेतनमानों तथा अन्य सेवाशर्तों का फैसला करने के लिए एक के बाद एक ट्रिबयूनल बैठाए और 1962 तक यही सिलसिला चला. 1964 में यह क्रम टूटा जब ए. आई. बी. इ. ए. ने मांगें हासिल करने के लिए सीधा संघर्ष करने का सही फैसला लिया. मजदूर वर्ग के नजरिये तथा सीधे संघर्ष के रास्ते पर चल कर बैंक कर्मचारियों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिससे बैंक मालिकान (बैंकर) द्विपक्षीय वार्ता पर बैठने को मजबूर हुए.

गहरा आघात

7. यह एक अच्छी शुरूआत थी, लेकिन ए. आई. बी. ई. ए. के नेता लड़खड़ा गए और मुद्दों के प्रति वर्गीय दृष्टिकोण अपनाने पर दृढ़ रहने की बजाए उन्होंने बैंकरों की साजिशों के सामने समर्पण कर दिया. वेतन में कुछ बढ़ोतरी के बदले उन्होंने बड़े पैमाने पर मशीनीकरण की स्कीम को स्वीकार कर लिया. ट्रिब्यूनल द्वारा थोपे गए अनुशासन संबंधी घातक प्रावधानों को भी यथावत् रखने की छूट दी. इस प्रकार बैंक कर्मचारियों के महान आंदोलन को इन नेताओं ने गहरा आघात पहुंचाया. यह 1966 की बात है. पिछले वर्ष ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों की शानदार हड़ताल—अद्वितीय और सबसे लम्बी हड़ताल (नवम्बर 1979—फरवरी 1980) ने मशीनीकरण के बारे में 1966 के द्विपक्षीय समझौते के असली अर्थ को उघाड़ कर रख दिया. ए. आई. बी. इ. ए. के नेताओं ने दिल्ली यूनिट को हड़ताल वापिस लेने का आदेश देकर इस संघर्ष को तोड़ने की गद्दारी का काम खुलकर किया. बाद के 1970 और 1979 के द्विपक्षीय समझौतों ने यह साफ कर दिया कि किस प्रकार इन नेताओं ने पहले द्विपक्षीय समझौते के पदचिन्हों पर चलते हुए एक के बाद एक, बैंक कर्मचारियों के बुनियादी हितों को बैंक मालिकान और सरकार के साथ मिलकर बलि चढ़ा दिया. मजदूर वर्ग का संघर्ष का रास्ता अपनाने की बजाए, जान बूझ कर मंहगाई भत्ते की दर में कटौती करने वाला फार्मूला स्वीकार करना, जिससे मंहगाई भत्ते पर उच्चतम सीमा की रोक भी मान ली गई, स्वैच्छिक पंच फैसले का दिखावा करके, मशीनीकरण कम्प्यूट्राइजेशन की प्रक्रिया को विस्तृत करके काम का बोझ बढ़ाने, कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि को निश्चित सहमति देना एक बार फिर यह संकेत करते हैं कि इन नेताओं ने किस प्रकार कर्मचारियों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. ये सब और कुछ न होकर निरी गद्दारी की मिसालें हैं.

आवाज का गला घोंटना

8. जबसे ये वर्ग-सहयोग के तहखाने में घुसे हैं, तबसे ये नेता बड़ी सतर्कता के साथ बाकी मजदूर-वर्ग से अलग हटने के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा कि सभी केंद्रीय ट्रेड-यूनियनों और दफ्तर-कर्मचारियों की फैडरेशनों द्वारा 1975 में दिल्ली में आयोजित वेतन-जाम विरोधी सम्मेलन में इनके भाग न लेने और इसी प्रकार के बंगलोर सम्मेलन (1979) में भाग तो लेने, परन्तु 14 सितम्बर 1979 को देश व्यापी हड़ताल करने से सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को, एक-दो राज्यों को छोड़कर, अमल में न लाने से जाहिर है.

9. इन नेताओं की शासक दल से मिली-भगत की हद का नमूना उस समय देखने को मिला, जब इन्होंने इस संगठन के प्लेट-फार्म को "आपातकाल" का स्वागत करने के लिए इस्तेमाल किया.

वर्ग सहयोग किस हद तक !

10. ये नेता 1966, से ही कर्मचारियों के आधारभूत हितों को नुकसान पहुंचाने वाले जो काम कर रहे थे, उनके खिलाफ स्वाभाविक-रूप से बैंक कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई. मतभेद

की इस आवाज का गला घोंटने के लिए इन नेताओं ने व्यवस्थित रूप से भिन्न विचारों के प्रतिनिधियों को संगठन से निकालना शुरू कर दिया, विभिन्न बैंकों और क्षेत्रों में समानान्तर, एडहॉक फूटपरस्त संस्थाएं तथा यूनियनें खड़ी करके विभाजन करना शुरू कर दिया. राज्य फैडरेशनों से हां में हां न मिलाने वाली यूनिटों की एफिलिएशन खत्म की गयी, उदाहरण के लिए—उड़िसा (1969), बिहार (1978 से सेन्ट्रल बैंक से शुरू करने और उसके बाद), आंन्ध्रा (1979), केरल (1980), अहमदाबाद (1979) यूनियन बैंक (1976 में-बम्बई और बाद में अन्य राज्यों में), युनाइटिड कमर्शियल बैंक (उड़िसा 1972, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली), रिजर्व बैंक (नई-दिल्ली, नागपुर, मद्रास, हैदराबाद, पटना, कलकत्ता). इस प्रकार के बहुत से उदाहरण देश के दूसरे भागों और बैंकों में मिलते हैं.

11. पश्चिमी बंगाल राज्य में, ए आई बी इ ए की यूनिट बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन नेवर्किंग कमेटी या जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाने से इन्कार कर दिया (पिछले तीन वर्षों में 3 या 4 बार के इलावा) और, एक साल पहले फैसला हो जाने के बावजूद न सिर्फ कान्फ्रेंस आयोजित नहीं की गई, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बल्कि इसके जनरल सेक्रेटरी—जो स्वयं अपनी बेस-यूनिट में पिछले तीन सालों से चुनाव नहीं जीत पाये, लेकिन बी. पी. बी. इ. ए. में अपने पद से बेशर्मी के साथ चिपके हुए हैं —ने अपनी मनमर्जी से 16 घटक यूनिटों तथा बी. पी. बी. इ. ए. के चार पदाधिकारियों—एक उपाध्यक्ष, दो ज्वाइंट सेक्रेट्री तथा एक सहायक कोषाध्यक्ष, को उनके पदों से हटाने का ऐलान कर दिया और इस प्रकार उन्हें ए. आई. बी. इ. ए. की जनरल कांउसिल से निकालने का आधार बना लिया है.

ए. आई. बी. ई. ए. नेतृत्व एकता को तोड़ने पर आमादा

12. सन 1966 में पहले द्विपक्षीय समझौते के समय से ही, संगठन के भीतरी मंचों पर बार-बार विरोध और एतराज उठाये जाने के बावजूद ए. आई. बी. इ. ए. के इन नेताओं और विभिन्न राज्यों और बैंकों में इनके समर्थक नेताओं ने न केवल आत्म-समर्पण करना जारी रखा, बल्कि इसे और भी बढ़ा दिया. आत्म-समर्पण की इस भूमिका के तर्क-संगत परिणाम-स्वरूप इन्होंने, ए. आई. बी. इ. ए. की दिसम्बर 1979 में बड़ौदा में आयोजित जनरल काउंसिल की मीटिंग में, ए. आई. बी इ. ए. और इसकी यूनिटों में सभी प्रकार के मतभेद का सफाया कर देने का फैसला किया ताकि संगठन पर इनका और इनकी मंडली का पूर्ण नियंत्रण कायम रह सके. इस प्रक्रिया में, ये बैंक कर्मचारियों की एकता व उनकी संगठनात्मक एकबद्धता को हर संभव तरीके से तोड़ने पर आमादा हैं ताकि ये बैंकरों और अपने स्वामियों (आकाओं) को ज्यादा कारगर तरीके से खिदमत कर सकें.

13. इस प्रकार पिछले दस वर्षों में इन नेताओं द्वारा हजारों कर्मचारियों को संगठन के बाहर खदेड़ दिया गया. अब वे दिन लद गये जब ए. आई. बी. इ. ए. का नाम बैंक कर्मचारियों की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाली एक ऐसी एकजुट संस्था का प्रतीक था, जो मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण, सिद्धांतों और आदर्शों के साथ जनवादी तरीके से काम करती हो. अब ए. आई. बी. इ. ए. अवसरवादियों, स्वार्थियों और ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड यूनियन अफसरशाहों की कुर्सियों के लिए लड़ाई का अखाड़ा बन गया है. इस संगठन की कार्यपद्धति आज एक गुट तक ही सीमित होकर रह गई है, बाकी लोगों को या तो हुक्म बजाना पड़ता है या संगठन छोड़ना पड़ता है और अगर कोई इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं कर पाता है तो उसे संगठन से निकाल दिया जाता है. जो लोग इन नेताओं के आदेशों को आंखें बंद करके मानने या संगठन छोड़ने से इकार करते हैं और अपने सही दृष्टिकोण पर कायम रहकर अपनी बात रखते हैं, उन्हें संगठन से निकालकर या उनकी एफिलिएशन खत्म कर देना ही आज मुख्य रुझान है.

नये संगठन का फैसला

14. यह सम्मेलन पूरी तरह आश्वस्त है कि ए. आई. बी. इ. ए. और उसकी राज्य यूनिटें इन सनकी नेताओं के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों को—उनके असली हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एकबद्ध करनेवाली और सार्थक संगठन नहीं रह गई है. इन नेताओं ने ए. आई. बी. इ. ए. के झंडे को अपमानित करके उसकी चिंधियाँ उड़ा दी है जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता. इसके पीछे अब और लगे रहना व्यर्थ है.

15. इसलिए, यह सम्मेलन पश्चिमी बंगाल के बैंक कर्मचारियों का आह्वान करता है कि ए. आई. बी. इ. ए. के नेताओं और हर बैंक में उनके पिट्ठुओं की भर्त्सना में उठ खड़े हों और ए. आई. बी. इ. ए. तथा उसकी राज्य यूनिटों से अलग होने का अपरिहार्य फैसला लें.

16. इस सम्मेलन में भाग लेनेवाली यूनियनें / एसोसिएशनें ए. आई. बी. इ. ए. की राज्य यूनिट बी. पी. बी. इ. ए. से संबंध-विच्छेद करने का फैसला लेती हैं.

बैंक कर्मचारियों के हित में

17. यह सम्मेलन यह निर्णय लेता है कि बैंक कर्मचारियों के एक ऐसे उपयुक्त जनसंगठन के स्थापित और गठित करने के लिए पहलकदमी की जाए, जो कि—वर्ग-सहयोग के रास्ते पर चलने से परहेज करेगा, —ट्रेड यूनियन कार्य प्रणाली में जनवादी तौर-तरीकों व सिद्धांतों से परिचालित होगा, —बैंक कर्मचारियों में सार्थक एकता स्थापित करेगा, संघर्ष के लिए एकता उनके वर्ग हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए मजदूर वर्ग का अंग होने के नाते उससे करीबी सहयोग के साथ काम करेगा, —ए. आई. बी. इ. ए. और उसकी राज्य यूनिटों पर काबिज घुटने-टेकू गुट द्वारा बैंक कर्मचारियों के भौतिक हितों को पहुंचाई गई गंभीर हानि मसलन—नौकरी की सुरक्षा, वेतन कटौती, मशीनीकरण, कम्प्यूटराइजेशन आदि के क्षेत्र में,

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

तमिलनाडु में काले अध्यादेशों के खिलाफ मजदूरों का प्रतिरोध

तमिलनाडु का मजदूर और किसान वर्ग इंदिरा सरकार द्वारा थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों जैसे काले अध्यादेशों का विरोध करने को उठ खड़ा हुआ है. पिछले दो महीनों में कई ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर लाखों मजदूरों व किसानों ने विरोध कार्यक्रमों में भाग लिया व सुरक्षात्मक नजरबंदी अधिनियम तथा अन्य काले अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की. इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलों से हड़तालों, सभाओं, प्रदर्शनों और सम्मेलनों की रिपोर्टें मिल रही है.

5 अक्तूबर को सीटू, एटक, डब्लू पी सी और टी.ए.टी.यू.सी. (जनता) के संयुक्त आह्वान पर मद्रास में सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में अन्य वक्ताओं के अलावा आर. उमानाथ ने भी भाषण दिया. इस सम्मेलन के आह्वान पर 14 अक्तूबर को 1 लाख से भी अधिक मजदूरों ने एक घंटे काम रोक कर प्रदर्शन किए.

कोयम्बटूर जिले में सीटू, एटक, टी.एन.टी.यू.सी. व के.एन.टी.यू.सी. के आह्वान पर 50 हजार से अधिक मजदूर चार घंटे की हड़ताल पर गए. कोयम्बटूर व चिरूपुर नगरों में विशाल प्रदर्शन हुए जिनमे हजारों मजदूरों ने भाग लिया.

थंजाबुर जिले में 30 सितम्बर को दो लाख खेतिहर मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल की तथा इस अध्यादेश के विरोध में सभाएं कीं. मदुरई जिले में नगर निगम, चमड़ा, सिगार तथा अन्य उद्योगों के मजदूरों ने 26 सितम्बर को काम रोका व प्रदर्शन किया. त्रिची जिले में 10 अक्तूबर को संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूरों ने अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किए.

सालेम में 24 सितम्बर को सार्वजनिक संस्थान बर्न एंड कम्पनी के मजदूर चार घंटे की हड़ताल पर रहे. अन्य इकाइयों के मजदूरों ने उनका साथ दिया व संयुक्त रूप से सभाएं व प्रदर्शन किए गए. 9 सितम्बर को ट्यूटीकोरिन जिले में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर एक सम्मेलन किया गया तथा 8 अक्तूबर को अध्यादेश विरोधी दिवस मनाया गया. कन्याकुमारी जिले में 22 अक्तूबर को हड़ताल की गई. इस पूरे समय के दौरान राज्य-भर में अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए सैकड़ों सभाएं व प्रदर्शन हुए.

20 नवंबर को निर्माण मजदूरों का अखिल भारतीय मांग दिवस

सीटू के आह्वान पर देशभर के निर्माण मजदूर 20 नवंबर को अपनी मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय मांग दिवस का आयोजन करेंगे. इनकी मुख्य मांगों में वेतन में वृद्धि, नौकरी में सुरक्षा, छंटनी पर रोक, निर्माण उद्योग में काम की स्थिति में सुधार लाने के लिए विस्तृत कानून, ठेका मजदूर पद्धति का खात्मा और ट्रेड यूनियन अधिकार आदि शामिल हैं.

इस दिन सीटू के यूनियन इस उद्योग के मजदूरों की समस्याओं पर रोशनी डालने के लिए सभाएं और प्रदर्शन करेंगी. इस आंदोलन के कार्यक्रम के प्रचार के लिए पर्चे व पोस्टर छापे जाएंगे. सभी मजदूर बिल्ले पहनेंगे जिन पर उनकी मांगें लिखी गई होंगी. जहां तक संभव है यह आंदोलन अन्य ट्रेड यूनियनों के सहयोग से ही किया जाएगा.

20 नवंबर को अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय निर्माण उद्योग में काम करने वाले कामरेडों ने 15 सितंबर को समर मुखर्जी की अध्यक्षता में कन्नानोर में हुई सभामें किया था. इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, बिहार और जम्मू-कश्मीर के लगभग 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यूनियन की गतिविधियों तथा मजदूरों की समस्याओं की समीक्षा के बाद सभा में इस कदम का आह्वान किया गया.

कर्नाटक में निवारक नजरबंदी अध्यादेश के खिलाफ सीटू द्वारा प्रदर्शन

सीटू की बंगलोर कमेटी के आह्वान पर 10 सितंबर को हजारों मजदूरों ने जुलूस की शक्ल में जाकर राज्यपाल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लागू किये गये सुरक्षा अध्यादेश अधिनियम के विरुद्ध एक ज्ञापन में मजदूरों ने अपील की है कि इस अध्यादेश ने राज्य में लागू न किया जाए क्योंकि यह ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ उन्हें कालाबाजारी और जमाखोर बताकर इस्तेमाल किया जाएगा.

सीटू के नेताओं एस. सूर्यनारायण राव, टी. एम. अनतराम, आर. श्रीनिवास और एन. एल. उपाध्याय के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट की तथा उन्हें यह ज्ञापन दिया. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल पर दबाव डालते हुए कहा कि हाल ही में मजदूरों ने अनिवार्य सेवा कानून के जो आम लोगों के हड़ताल के अधिकारों को कम करता है के विरोध में 18 अगस्त को एक आम हड़ताल की थी. इसके बावजूद सरकार ने यह अध्यादेश जारी करने का कदम उठाया है इसमें मजदूर बहुत हैरान है.

छटी योजना की बुनियादी नीतियों की सीटू द्वारा आलोचना

11 अक्तूबर को नई दिल्ली मे योजना मंत्री एन. डी. तिवारी के साथ हुई एक बैठक में सीटू प्रतिनिधियों ने छटी योजना के बुनियादी दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि योजना का वास्तविक नतीजा उसके उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत रहेगा. इसलिए सीटू ने इन नीतियों को पूरी तरह से बदलने की मांग की.

इस बैठक का आयोजन खासतौर से सीटू के विचार जानने के लिए किया गया क्योंकि केंद्रीय ट्रड यूनियनों के साथ सितंबर में हुई इसकी बैठक में सीटू को गलती के कारण नहीं बुलाया गया था.

सीटू की तरफ से महासचिव पी. राममूर्ति, सचिव एम के पंधे और सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने इस बैठक में भाग लिया.

पी. राममूर्ति ने छटी योजना की रूपरेखा पर विस्तार से बताया और कहा कि नेशनल डवेलपमेंट काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में ड्राफ्ट पेश करने से पहले सरकार को चाहिए था कि वो ट्रेड यूनियनों से विचार विमर्श करती. उन्होंने कहा कि यूनियनों के साथ योजना के ड्राफ्ट के बारे में विचार विमर्श केवल औपचारिकता मात्र है. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श केवल श्रम नीतियों पर ही किया जाता है लेकिन ट्रेड यूनियनें आर्थिक नीतियों पर भी अपने विचार पेश करना चाहती हैं.

पिछली योजनाओं के नतीजों को मध्ये नजर रखते हुए राममूर्ति ने कहा कि इन योजनाओं ने केवल विकास में असमानता और कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों में पूंजी के केंद्रीयकरण को ही बढ़ावा दिया है. उन्होंने इस वास्तविकता पर ध्यान आकर्षित कराया कि देश की कुल पेड-अप पूंजी का 80 प्रतिशत भाग इन 100 बड़े औद्योगिक घरानों के पास ही एकत्रित है. भूमि सुधारों को लागू कराने की अनुपस्थिति के कारण जो फंड योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं उनको ग्रमीण अमीरों ने ही हड़पा है.

राममूर्ति ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने बालों की संख्या इन योजनाओं के तहत लगातार बढ़ती ही गई है. उन्होंने इसे साबित करने के लिए तथ्य भी पेश किए.

सीटू, देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि की आलोचना करती है जिनके कारण देश का औद्योगिक विकास कम होता जा रहा है. उन क्षेत्रों में भी जहां देशीय तकनीकी उपलब्ध है सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यापार करने की इजाजत दे रही है. भारतीय सरमायदारों द्वारा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ विदेशी सहयोग के लिए किए गए समझौतों के कारण देश की बहुमूल्य राशि देश से बाहर जा रही है. राममूर्ति ने निर्यात की ओर बेतहाशा झुकाव और बजट के स्रोतों से निर्यात-कर्त्ताओं को दी गई भारी रियायतों की निंदा की. उन्होंने नोजना का विश्व बैंक पर बढ़ती निर्भरता के और विश्व बैंक किस प्रकार योजना नीतियों में दखलंदाजी कर रहा है के बारे में उल्लेख किया. आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बजाय देश लगातार विदेशी ऋणों पर निर्भर होता जा रहा है.

सीटू ने भारत में अनुसंधान व विकास के काम की आलोचना की और कहा जो भी काम भारत में किया गया है उसका सरकार ने कोई उपयोग नहीं किया है. वैज्ञानिक व तकनीकज्ञ इससे निराश हो रहे हैं और उनमें से अनेक देश छोड़कर जा रहे हैं.

राममूर्ति ने सरकार की वेतन जाम नीति की भी आलोचना की और कहा कि बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति से मजदूर-वर्ग का वास्तविक जीवन-स्तर लगातार गिरता जा रहा है. सभी योजनाओं में में अतिरिक्त करों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भरता आई है.

प्रबंध में मजदूरों द्वारा भाग लेने के बारे में बोलते हुए राममूर्ति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली मजदूरों के प्रबंध में भाग लेने का मजाक कर रही है. सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रशासन ने मजदूरों द्वारा वास्तव में भाग लेने के लिए कोई रुचि नहीं दिखायी है. इसलिए ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों द्वारा भाग लेने की झूठी योजना को स्वीकार नहीं किया है.

राममूर्ति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने वाले बुरे कामों को यदि मजदूर खुले आम जाहिर कर देता है तो प्रबंधक उसे परेशान करते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ऐसे मजदूरों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी तब तक वे कैसे सार्वजानिक क्षत्रों में हो रहे गलत कामों पर प्रकाश डालने में समर्थ हो सकते हैं.

सीटू प्रतिनिधियों ने इस्पात उद्योग में छः अध्ययन दलों की रिपोर्टों व सार्वजनिक उद्योगों में कार्यप्रणाली के बारे में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को लागू न करने की आलोचना की है. इसलिए मजदूरों का सरकार की विश्वसनीयता पर से विश्वास हटने लगा है. इसलिए यह आवश्यक है कि इन रिपोर्टों को लागू कराने के लिए तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए.

सीटू प्रतिनिधियों ने मंत्री से अनुरोध किया कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले इन विचारों को मध्येनजर रखा जाए.

आई. एल. ओ. कनवेंशन कमेटी : एक मजाक

आई. एल. ओ. कनवेंशन कमेटी का 15वां अधिवेशन 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ जो कोई संतोषजनक हल निकालने में नाकामयाब रहा क्योंकि भारत सरकार के प्रतिनिधि इस कमेटी के विचाराधीन आई. एल. ओ. के किसी भी कनवेंशन के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाने के लिए तैयार नहीं थे.

श्रम-मंत्रालय के सचिव के. एस. रघुपति ने इस बैठक की अध्यक्षता की.

कमेटी की पिछली बैठक में एक मजदूर द्वारा अधिकतम कितना वजन उठाये जाने से संबंधित कनवेंशन को लागू करवाने के लिए मई 1980 की तारीख तय की गई थी. लेकिन यातायात, खाद्यान तथा रेल विभाग ने माल ढोने के लिए अधिकतम 55 किलोग्राम वजन तय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं. ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अनेक मंत्रालयों द्वारा दिये गये तर्कों की कटु आलोचना की और कनवेंशन को फौरन लागू करने की मांग की. निजी क्षेत्र मालिकान के प्रतिनिधियों ने भी इसे लागू करने की मांग की है. इसलिए इस बैठक के अध्यक्ष ने इस कनवेंशन को लागू करने के लिए एक नोट तैयार कराना स्वीकार किया जिसे अगली बैठक जो राष्ट्रीय सम्मेलन के समय होगी में विचार के लिए रखा जाएगा.

ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कृषि में श्रम निरीक्षण से संबंधित कनवेंशन को नहीं अपनाए जाने की भी आलोचना की व उन्होंने बताया कि कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन को भूमिपति लागू नहीं कर रहे हैं.

सीटू प्रतिनिधि ने आई. एल. ओ. द्वारा भारतीय नाविकों के लिए निर्धारित किए गए वेतन को लागू न करने के प्रश्न को उठाया. प्रबंधक पिछली बैठक में तय की गई तारीख तक बताने में असफल रहे.

65वें आई. एल. ओ. अधिवेशन में स्वीकृत कनवेंशनों व सिफारिशों के बारे में श्रम मंत्रालय ने एक नोट तैयार किया है जो वास्तव में यह स्वीकार करता है कि कार्यरूप में कोई भी कनवेंशन लागू नहीं की जा सकी. नोट में यह खुलकर व्यक्त किया है कि "भारत के मालिकान व मजदूरों को कनवेंशन में निहित सभी अधिकार प्राप्त हैं. उन्हें यूनियनों व फेडरेशनों में पहले मंजूरी लिए बगैर व कोई मूल प्रतिबंध के बगैर संगठित होने की पूरी स्वतंत्रता है."

सीटू प्रतिनिधि ने कहा कि भारत में मालिकान को तो एसोसिएशन बनाने का पूरा अधिकार हो सकता है, मजदूरों को नहीं. उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) नियम की आलोचना की है क्योंकि यह नियम इस बात पर जोर देता है कि एसोसिएशन के नियमों में कोई भारी चरित्र का संशोधन सरकार से पहले इजाजत लेने पर ही हो सकता है. इन नियमों में यह भी निहित है कि एसोसिएशन सरकार से पहले अनुमति लिए बगैर कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सकती और एसोसिएशन विदेशी अधिकारियों से कोई पत्र व्यवहार नहीं कर सकती सिवाय सरकार के जिसे यह रोकने तक का अधिकार है.

सरकारी नोट में कहा गया है कि "आई. एल. ओ. विशेषज्ञ कमेटी ने मान्यता देने के लिए 'बाहरी लोगों' पर प्रतिबंध का विरोध किया है. बाहरी लोगों पर प्रतिबंध संगठन के अधिकार पर कोई संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन केवल मान्यता के लिए एक पूर्वशर्त होने के नाते यह सीमित है. फिर भी, विशेषज्ञ कमेटी ने लगता है इसे कनवेंशन नं० 87 का उल्लंघन माना है."

कुछ लंबे तर्कों के बाद सरकारी नोट कहता है कि "इसे ध्यान में रखते हुए यह साफ़ जाहिर है कि देश में मौजूद कानून और व्यवहार कनवेंशन 87 या 98 को अपनाए जाने की इजाजत नहीं देते हैं." ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस रवैये की तीखी आलोचना की और आई. एल. ओ. कनवेंशनों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए मौजूदा कानून और व्यवहार में परिवर्तन करने की मांग की. लेकिन श्रम-मंत्रालय का प्रवक्ता सरकार के दृष्टिकोण के समर्थन में संतोषजनक तर्क नहीं दे सका. उनका रवैया इस मसले पर विचार को किसी न किसी कारण से देर करने का था.

सरकार के इस दृष्टिकोण पर नवल टाटा ने कहा कि सरकार केवल उन्हीं कनवेंशनों पर अपना मतदान करे जो भारत में लागू हो सकें. किंतु ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इस तर्क पर अपना विरोध जाहिर किया.

इस प्रकार यह बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. कुछ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार इस कमेटी की बैठक को आई. एल. ओ. के नियमों को पूरा करने के लिए एक औपचारिकता के रूप में ले रही है.

इस बैठक में सीटू का प्रतिनिधित्व एम. के. पंधे ने किया व अन्य ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि थे—कांति मेहता (इंटक), बी. एन. राजहंस (एच. एम. एस.), टी. एन. सिद्धांत (एटक) और प्रभाकर घाटे (बी. एम. एस.).

सीटू के प्रतिनिधि

1. **सेंट्रल एड्वाइजरी काउंसिल आफ चाइल्ड लेबर:**
सुशीला गोपालन, उपाध्यक्ष, सीटू.

2. **सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड:**
ई. बालानंदन, सचिव, सीटू.

3. **सेंट्रल एड्वाइजरी कमेटी आफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट:**
अहिल्या रांगणेकर.

4. **सेंट्रल एड्वाइजरी कमेटी आफ बीड़ी वर्कर्ज:**
1. सी. कन्नन, उपाध्यक्ष, सीटू. और
2. निजामुद्दीन (पश्चिम बंगाल)

समाचार-पत्र कर्मचारियों द्वारा सरकार को चेतावनी

कानफेडरेशन आफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसी एम्पलाईज आर्गेनाइजेशन की नैशनल कमेटी ने देश भर के समाचार-पत्र व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को कहा है कि यदि सरकार पालेकर ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय में कानफेडरेशन द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं करती तो उन्हें अनिश्चित-कालीन हड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए.

6 अक्तूबर को बंगलौर में हुई बैठक के बाद कानफेडरेशन के अध्यक्ष एस वाई कोलहट्कर ने एक प्रैस कांफ्रेंस में मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि समाचारपत्र व समाचार एजेंसियों के कर्मचानियों के सब्र का घड़ा भर चुका है और यदि शीघ्र ही उनकी भावनाओं के अनुरूप उनके वेतनमानों में संशोधन न किया गया तो इस उद्योग में भारी अशांति फैल जाएगी जिसकी जिम्मेदारी पूरी तौर से सरकार व मालिकों पर होगी.

नैशनल कमेटी की बैठक से पहले 4 व 5 अक्तूबर को आल इंडिया न्यूज-पेपर एम्पलाईज फैडरेशन का बारहवां वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ. इसके साथ साथ फेडरेशन आफ पी टी आई एम्प-लाईज यूनियन की जनरल काउंसिल की भी बैठक में डेलीगेटों ने कानफेडरेशन को पालेकर ट्रिब्यूनल के निर्णय में समुचित संशोधन करवाने के लिए देशव्यापी संघर्ष चलाने का सुझाव दिया.

इससे पहले समाचारपत्र व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों ने 30 सितंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने के कानफेडरेशन के आह्वान को अभूतपूर्व समर्थन दिया. समाचारपत्र कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में यह हड़ताल असाधारण रूप से सफल रही. इस दिन न केवल बड़े शहरों के प्रमुख अखबार बंद रहे बल्कि जिलों व कस्बों के छोटे अखबार भी प्रकाशित न हुए. राष्ट्रीय स्तर की चारों समाचार एजेंसियों ने भी हड़ताल में पूरा भाग लिया.

सीटू द्वारा एच. एस. सी. एल. में छंटनी का विरोध

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने 3 अक्टूबर को निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज एच. एस. सी. एल. के प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को बड़ी संख्या में अतिरिक्त घोषित कर उनकी छंटनी करने के कदमों की तीव्र निंदा करती है. कुद्रेमुख में 239 मजदूरों को छंटनी के नोटिस दिए जा चुके हैं जिनमें से 100 मजदूर 'निपुण' श्रेणी में में आते हैं.

सीटू ने प्रबंधकों को सुझाव दिया था कि इन अतिरिक्त मजदूरों को एच. एस. सी. एल. के अंतर्गत चल रही सूपा तथा अन्य परियोजनाओं में लगा दिया जाए जिससे कि इनके रोजगार की रक्षा हो सके. किंतु प्रबंधकों ने इस सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया.

एच. एस. सी. एल. में मजदूरों की कुल संख्या 22 हजार है. किंतु 50 हजार से अधिक मजदूर ठेकेदारी पद्धति के अंतर्गत काम कर रहे हैं. एच. एस. सी. एल. के प्रबंधकों की नीतियों के अंतर्गत एक ओर तो अधिक से अधिक काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है तथा दूसरी ओर सैकड़ों मजदूरों को अतिरिक्त घोषित कर नौकरी से निकाल दिया जाता है.

सचाई यह है कि एच. एस. सी. एल. के भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर असीमित धन कमाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी घाटे पर चलती है. अपने भ्रष्ट आचरण पर पर्दा डालने के लिए प्रबंधक यह अफवाह फैला रहे है कि मजदूरों की उत्पादकता कम है. सीटू इस बेबुनियाद झूठ की निंदा करती है और मांग करती है कि सरकार एच. एस. सी. एल. प्रबंधकों द्वारा ठेकेदारों के स्वार्थों का पोषण करने के लिए कंपनी का अहित करने के प्रयत्नों की निष्पक्ष जांच करे.

सीटू केंद्रीय इस्पात मंत्री से अपील करती है कि वे छंटनी के आदेशों को वापिस लेने तथा कारखाने के सभी काम विभागीय मजदूरों से करवाने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं.

सीटू एच. एस. सी. एल. में काम करने वाली सभी यूनियनों से भी अपील करती है कि वे प्रबंधकों की इस बदला लेने वाली कार्रवाई का विरोध करें जिससे कि उन्हें छंटनी आदेश वापिस लेने पर मजबूर होना पड़े.

जम्मू व कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन

जम्मू और कश्मीर के निम्न वेतन सरकारी कर्मचारियों की चौथी कानफ्रेंस 8 व 9 अक्तूबर को श्रीनगर में संपन्न हुई. कानफ्रेंस का उद्घाटन करते हुए सीटू महासचिव सांसद पी. राममूर्ति ने प्रतिनिधियों से सरकार की मजदूर-वर्ग विरोधी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ और आम जनता की फौरी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.

फेडरेशन के महासचिव संपथ प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सांप्रदायिकतावादी व क्षेत्रीयतावादी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए अपने ट्रेड यूनियन का जनवादी ताकतों की सहायता करके जनता की जीविका पर होने वाले हमलों का मुकाबला करने का आह्वान किया. इस कानफ्रेंस में संपथ प्रकाश को फेड-रेशनका अध्यक्ष चुना गया.

किसका शासन है : दिल्ली या वेस्टमिन्स्टर का ?

—जिम स्लाटर

(यह लेख नेशनल यूनियन आफ सीमैन, लंडन के मुखपत्र 'दि सीमैन' के मार्च 1980 के अंक से लिया जा रहा है. इसके लेखक यूनियन के महासचिव हैं)

ब्रिटिश जहाजों पर काम कर रहे गैर-ब्रिटिश नाविकों की सेवा शर्तों पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट डिपार्टमैंट आफ ट्रेड द्वारा 1977 में प्रकाशित कर दी गई थी. इसकी मुख्य सिफारिश थी कि ब्रिटिश जहाजों पर काम कर रहे सभी नाविकों को, चाहे वे किसी भी देश या जाति से संबंध रखते हों, बराबर मजदूरी मिले.

नेशनल यूनियन आफ सीमैन इस सुझाव को अपना पूरा समर्थन देता है. वास्तविकता तो यह है कि हमारी पहल पर ही इस ग्रुप को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. रिपोर्ट के निष्कर्षों को ब्रिटिश जहाजों के मालिकों व पिछली सरकार दोनों ने ही अपनी अनुमति दे दी थी तथा सुझावों को अमली जामा पहनाने में पूरा सहयोग दिया था.

किंतु कुछ और देशों की सरकारें (विशेषकर भारत सरकार) इन प्रयत्नों का विरोध कर रही हैं. उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश जहाजरानी में काम करने वाले विदेशी नाविकों में सबसे अधिक संख्या भारतीय नाविकों की है.

भारत सरकार का विरोध संभवतः इस आधार पर है कि नाविकों को ब्रिटिश स्तर से मजदूरी मिलने से भारत में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी. इस तथाकथित दलील में चाहे कोई दम हो या न हो, सच्चाई यह है कि बहुत से ब्रिटिश जहाजों पर ब्रिटिश कानूनों के बजाय भारतीय कानून ही लागू हो रहे हैं. दूसरे शब्दों में ब्रिटिश सरकार, जहाजों के मालिक व नाविकों के सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोणों को नकारा जा रहा है और भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है.

भारत सरकार की इच्छा है की भारतीय नाविकों को अधिक मजदूर देने के बजाय इस अतिरिक्त धन से एक सहायता कोष बना दिया जाए जिसका ब्रिटिश जहाजों पर काम करनेवाले नाविकों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय नाविकों के हित में प्रयोग हो. इस सुझाव के अनुसार इस धन को भारत में पूंजी निवेश के रूप में प्रयोग किया जाएगा तथा इससे मिलने वाले ब्याज से सहायता कोष चलाया जाएगा इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में नाविकों की मजदूरी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को 'सुधारने' में किया जाएगा. वर्किंग ग्रुप की सिफारिश में इस प्रकार की कोई बात न थी.

इसी प्रकार का एक कोष 1975 से पाकिस्तान में चल रहा है. वहां यह राशि सरकारी संस्थान पाकिस्तान शिप्पिंग कार्पोरेशन में लगाई जाती है. इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से यह ब्रिटिश धन ब्रिटिश जहाजरानी के प्रतियोगियों को लाभान्वित कर रहा है. यह अजीब बात है कि हम अपना धन अपने प्रतियोगियों को देकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं.

मुझे आश्चर्य होता है कि वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है. परिणामस्वरूप भारतीय नाविकों को अपनी सरकार के इस रूख के कारण प्रति माह अपनी जायज मजदूरी से 60 पौंड कम मिलता है. मैं सभी नाविकों को बराबर मजदूरी मिलने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हूं तथा इस मजदूरी को किसी और कोषादि के रूप में इस्तेमाल करने के विरुद्ध हूं.

वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट तथा इसकी सिफारिशों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति के पूरे सवाल की इस वर्ष समीक्षा की जानी है. मेरा दृढ़ विचार है कि भारत या किसी देश की सरकार को इस मामले पर अपनी शर्तें लादने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

भारत सरकार को साफ शब्दों में यह बता दिया जाना चाहिए कि नाविकों द्वारा किए गए काम की मजदूरी केवल नाविकों को ही दी जाएगी तथा इसे किसी अन्य कोष में नहीं डाला जाएगा. ब्रिटेन के जहाजों पर ब्रिटिश कानून लागू होते हैं या भारत सरकार के आदेश इस मुख्य सवाल का फैसला शीघ्र ही किया जाना चाहिए.

भारत सरकार ही जिम्मेदार

जिम स्लाटर के विचारों का समर्थन करते हुए फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया के महासचिव आशुतोष बनर्जी ने 25 जुलाई को वक्तव्य दिया. "ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी जहाजों पर भारतीय नाविकों की रोजगार संभावनाओं में लगातार कमी आने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है." आशुतोष बनर्जी ने आगे बताया कि ब्रिटिश जहाजों में नौकरी की संभावनाओं में लगातार वृद्धि होने से आशंकित हो भारत सरकार काफी समय से ब्रिटिश जहाजरानी के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैं अख्तियार कर रही थी. इस रवैये के कारण ही वह ब्रिटिश सरकार व ट्रेड यूनियनों के काम में हस्तक्षेप कर रही थी इसका नतीजा यह हो रहा है कि जहां एक ओर भारत सरकार अपने 38 हजार से भी अधिक पंजीकृत लेकिन बेकार नाविकों को काम देने में असमर्थ है वहां दूसरी ओर विदेशी जहाजों पर भी भारतीय नाविकों के लिए नौकरियों की संभावनाएं कम होती जा रहीं हैं.

इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि भारत सरकार के पास ऐसी कोई भ्रष्टाचार-रहित मशीनरी नहीं है जो आई. टी.

[शेष पृष्ठ नौ पर]

गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों द्वारा 18 नवंबर से लगातार हड़ताल की तैयारी

जल परिवहन में काम करने वाली चारों राष्ट्रीय यूनियनों—वाटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन आफ इंडिया, आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्ज फेडरेशन, इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डाक वर्कर्ज फेडरेशन तथा पोर्ट डाक एंड वाटरफ्रंट वकर्ज फेडरेशन—के साथ समझौता हो जाने के बाद भारत सरकार ने चारों यूनियनों के प्रतिनिधियों को लेकर एक बाइपार्टाइट वेज नैगोसियेशन मशीनरी बनाई. यूनियनों के प्रतिनिधियों ने गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों के वेतनमानों व अन्य सुविधाओं में बेहतरी लाने के मुद्दों पर समझौता करने की पूरी कोशिश की. इस उद्देश्य से उन्होंने पिछले पांच महीनों में बातचीत के लिए हुई प्रत्येक बैठक में भाग लिया. किंतु मालिकों के जिद्दी रवैये के कारण कोई फैसला न हो पाया तथा चारों फेडरेशनों को इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा कि इस द्विपक्षीय बातचीत को जारी रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा.

सरकार के चारों फैडरेशनों से हुए समझौते के अनुसार नये वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं को 1 जनवरी 1980 से लागू किया जाना था क्योंकि कई महीने बातचीत करने में समाप्त हो गए हैं इसलिए स्वाभाविक ही है कि गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों में अशांति व्याप्त हो गई है. यह गुस्सा बढ़ रहा है और संभव है कि वह बड़े बंदरगाहों पर औद्योगिक शांति को भंग कर दे.

चारों फेडरेशनों ने 10 अक्तूबर को एकमत से यह निर्णय लिया है कि सरकार, गोदी व बंदरगाह प्रशासन तथा गोदी मालिकों को सूचित किया जाए कि यदि मजदूरों द्वारा दाखिल किए गए मांगपत्र पर शीघ्र कोई उचित फैसला न लिया गया तो 18 नवंबर को सभी बड़े बंदरगाहों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी.

प्रस्ताव में चारों फेडरेशनों ने आशा व्यक्त की है कि सरकार शीघ्र ही मामले में हस्तक्षप करेगी तथा बातचीत द्वारा समझौता करवाने में मदद करेगी.

नाविक...

[पृष्ठ आठ से आगे]

एफ. में पड़े विशाल धन को वर्तमान सीफेयरर वैलफेयर फंड सोसाईटी सैल के द्वारा भारतीय नाविकों के हित में खर्च करे. 1973 से हमारी ओर से लगातार सूचना मांगे जाने के बावजूद इस कोष के प्रशासनिक अधिकारी ने अपने लेखा विवरण को नाविकों या जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है. लगभग सभी बड़ी भारतीय बंदरगाहों में नाविक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इन प्रदर्शनों पर कोई ध्यान देने के बजाय भारत सरकार ने अब यह अधिसूचना जारी की है कि अगस्त 1980 से इस कोष में से किसी नाविक को कोई धन न दिया जाए.

बेकार भारतीय नाविकों को इस समय रोजगार व बराबर मजदूरी की आवश्यकता है. वे इस प्रकार के किसी सहायता कोष में विश्वास नहीं करते क्योंकि इस कोष का इस्तेमाल जरूरतमंद नाविकों को सहायता पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता. भारत सरकार को चाहिए कि वह विदेशी जहाजों में भारतीय नाविकों की रोजगार संभावनाएं बढ़ाने में सहयोग करे तथा दूसरे देशों के धन के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के प्रयत्न छोड़ दे. इस प्रकार के तरीकों से विदेशों में भारतीय छवि बिगड़ती है.

सोवियत संघ के मजदूर वर्ग व जनता को शुभकामनाएं

ऐतिहासिक अक्टूबर क्रांति की 63वीं वर्षगांठ के मौके पर सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज व सीटू मजदूर सोवियत संघ के मजदूर वर्ग और जनता के समाजवादी निर्माण में उनकी भारी उन्नति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजती हैं.

सोवियत संघ में प्रशंसनीय वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों ने अमेरिका को कई तरह से मात दे दी है. जब पूंजीवादी पद्धति गहरे आर्थिक संकट में डूबी है, सोवियत संघ में लगातार आर्थिक उन्नति उन सबके लिए जो समाजवाद की पूंजीवाद पर विजय की प्रशंसा करते हैं, एक गौरव का विषय है.

भारत और सोवियत संघ की जनता में बढ़ रहे दोस्ताना संबंधों से सीटू प्रसन्न है और कामना करती है कि ये आनेवाले दिनों में और मजबूत होंगे.

समाजवाद के आगे निर्माण और बिश्व शांति की रक्षा में सोवियत संघ के मजदूर वर्ग और जनता की और अधिक विजयों के लिए सीटू कामना करती है.

सीटू आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज को शुभकामनाएं भेजती है. और अपना विश्वास व्यक्त करती है कि भविष्य में ए. यू. सी. सी.-टी. यू. और सीटू में विरादराना संबंध लगातार बढ़ते रहेंगे.

जूट मजदूरों का अखिल भारतीय फेडरेशन

27 सितंबर को कानपुर में पहले अखिल भारतीय जूट मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संसद सदस्य नीरेन घोष ने घोषणा की. "हमारा संघर्ष एकाधिकारी पूंजी को सीधी चुनौती है. हम केवल जूट उद्योग में काम कर रहे 3 लाख मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि 40 लाख जूट उत्पादक किसानों व उनके परिवारों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. कुल मिलाकर यह संख्या 2 करोड़ हो जाती है. अखिल भारतीय स्तर पर इस फेडरेशन के गठन से इस उद्योग में चल रहे ट्रेड यूनियन आंदोलन और भी सुगठित व मजबूत हो जाएगा."

दो दिन के इस सम्मेलन में 9 राज्यों से आए 179 डेलिगेटों ने भाग लिया व अखिल भारतीय जूट मजदूर फेडरेशन का गठन किया. सम्मेलन के स्थान का नाम कानपुर के मशहूर ट्रेड यूनियन नेता स्व० रामआसरे के नाम पर रखा गया था जिनकी 1973 में जूट मजदूरों की लंबी हड़ताल के दौरान हृदयगति रूक जाने से मृत्यु हो गई थी.

नीरेन घोष ने आगे बताया : "यह एक राजनीतिक संघर्ष भी है. पूंजीपति वर्ग चाहता है कि मजदूर राजनीति से दूर रहें जिससे कि उनका वर्ग-शासन चलता रहे. किंतु हमारा मत है कि मजदूर को राजनीतिक रूप से भी जागरूक रहना चाहिए क्योंकि जब तक देश में किसान-मजदूर राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक मजदूर सही मानों में स्वतंत्र नहीं हो सकता."

सम्मेलन में 7-सदस्यीय अध्यक्ष मंडल का गठन हुआ जिसने सम्मेलन की कार्यवाही को विधिवत चलाया. इसके सदस्य थे—मुहम्मद इस्माइल, मुहम्मद अमीन, गंगाधर रेड्डी, आर.एस. तिवारी, पीयूस दास, रवि सिन्हा व जईफ.

सम्मेलन की संचालन समिति के संयोजक कमल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में जूट उद्योग के आरंभ व जूट मजदूरों के आंदोलन के इतिहास को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि पहली जूट मिल की स्थापना हुगली में 1855 में हुई. 1947 के बाद के समय में 13 एकाधिरारी घरानों ने जूट उद्योग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की स्थापना के बाद अब सार्वजदिक क्षेत्र की एक इकाई भी इस उद्योग में स्थापित हो गई है.

1922 में अपनी स्थापना के बाद बंगाल जूट वर्कर्ज यूनियन का गौरवशाली इतिहास रहा है. 1929 में इस उद्योग में एक बड़ी हडताल हुई जो 39 दिन तक चली. इस लबे संघर्ष से मजदूरों को महत्त्वपूर्ण लाभ मिले. उनके काम के घंटों की संख्या 64 घटे प्रति सप्ताह से घटकर 54 घंटे प्रति सप्ताह हो गई तथा दंडित करने व भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पद्धतियों को समाप्त कर दिया गया. ट्रेड यूनियन अधिकारों को मान्यता मिली तथा महिला कामगारों को पहली बार प्रसूति छुट्टी जाने का अधिकार मिला. किंतु यह यूनियन कुछ वर्षों तक ही चल पाई. इसका स्थान बंगाल चटकल मजदूर यूनियन ने ले लिया जो जूट मजदूरों के संघर्ष का केंद्र बन गई. उस नए संगठन के नेतृत्व में जूट उद्योग में एक और बड़ी हड़ताल हुई जिससे सो मिलें प्रभावित हुई. यह हड़ताल 74 दिनों तक चली किंतु इसे अभूतपूर्व दमन का सहारा लेकर कुचल दिया गया.

संचालन समिति के संयोजक ने बताया कि इंडियन जूट मैनुफैक्चरर्स की स्थापना 1884 में हुई 1902 में इसका नाम बदलकर इंडियन जूट मिल्ज एसोसियेशन रख दिया गया. यह संस्था अग्रेजी शासन काल से ही सक्रिय है तथा जूट मिल मालिकों की गतिविधियों को समन्वित करती है. 1947 के बाद भी जूट कंपनियों से होने वाले लाभ का बड़ा अंश ब्रिटेन जाता रहा और भारत सरकार इस बारे में निष्क्रिय रही. जूट मजदूरों के संघर्ष चलते रहे. किंतु मिल मालिकों व कांग्रेस सरकार की मिली जुली शक्ति के आगे ये संघर्ष विशेष सफलता न पा सके. तथा इस कारण मजदूरों के काम करने के हालात में कोई परिवर्तन न हो पाया.

पहली वामपंथी मोर्चा सरकार बनने से जूट मजदूरों के आंदोलन में नई जान आ गई किंतु एकता के अभाव में यह चेतना मजबूत आंदोलन के रूप में सामने न आ पाई. 1968 की हड़ताल में इंटक ने भाग लेने से इंकार कर दिया. इस बीच पश्चिम बंगाल में वामपंथी ताकतें आगे बढ़ती गई. दूसरी वामपंथी मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान 1969 में हुई हड़ताल में इंटक को भी भाग लेना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप जूट मालिकों को ऐसी कई मांगों को मानना पड़ा जो उन्होंने एक वर्ष पहले अस्वीकार कर दी थीं. अपनी एकता, संघर्ष व राजनीतिक हालात का सही फायदा उठाते हुए जूट मजदूर ओप-निवेशिक मजदूरी को स्तरों को मूलभूत रूप से बदलने में सफल हुए जो स्तर आजादी के बाद भी जूट मिल मालिक बनाए रखे हुए थे. अब अन्य औद्योगिक मजदूरों के बराबर मजदूरी पाने का जूट मजदूरों का संघर्ष सही मानों में आरंभ हुआ.

1972 में जूट मजदूरों ने उद्योग-स्तर पर एक बार फिर हड़ताल करने का आह्वान किया जिसके फलस्वरूप मालिकों को उनकी मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ी. इस हड़ताल के बाद पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में हुए जूट मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन में जूट मजदूरों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने का विचार सामने आया.

पश्चिम बगाल में अर्द्ध-फासिस्ट आतंक व इमर्जेंसी शासन समाप्त होने व वामपंथी मोर्चे के सत्तारूढ़ होने के बाद 50 दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई. इस हड़ताल से जूट मजदूर 486.07 रु० न्यूनतम मजदूरी पाने में सफल हुए. पश्चिम बंगाल का मजदूर वर्ग वामपंथी मोर्चा सरकार को अपना हितैषी मानता है. पिछली कांग्रेसी सरकारों के मजदूर विरोधी रुख को नकारते हुए वर्तमान सरकार ने यह घोषणा की है कि ट्रेड यूनियन व जनवादी आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी. कमल सरकार ने बताया कि वामपथी सरकार की सक्रिय सहायता के फलस्वरूप मजदूर वर्ग ने कई महत्त्वपूर्ण जीतें हासिल की हैं.

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए लक्ष्मी सहगल ने कहा : "पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता व सीटू की रहनुमाई के कारण जूट मजदूर अन्य कपड़ा मजदूरों के मुकाबले अधिक संगठित व मजबूत है"

गंगाधर रेड्डी (आंध्र प्रदेश) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लंबी बातचीत के बाद नई वेज बोर्ड कमेटी ने यह स्वीकार कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों की मजदूरी में हुई वृद्धि आंध्र-प्रदेश में भी लागू की जाएगी. एटक के आर. एस. तिवारी (मध्य प्रदेश) ने कहा कि केवल एक कारखाने के प्रबंधकों ने पश्चिम बंगाल के स्तर पर मजदूरी देना स्वीकार नहीं किया है. पीयूष नाग (त्रिपुरा) ने त्रिपुरा राज्य में जूट मजदूरों के आंदोलन को रेखांकित करते हुए विवरण दिया कि हाल ही के दंगों में पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने में जूट मजदूरों ने कितना योगदान दिया. गुणाधार गोगोई (असम) ने बताया कि वर्तमान असम आंदोलन से जूट मजदूरों को कितना नुक्सान हुआ है.

सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए सांप्रदायिक झगड़ों, बाढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल की वामपंथी जनवादी सरकारों की रक्षा तथा इंदिरा सरकार द्वारा देश पर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जैसा काला अध्यादेश थोपे जाने आदि कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए.

सम्मेलन में 34 सदस्यों की वर्किंग कमेटी व 16 सदस्यों की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया. इसके अध्यक्ष लक्ष्मी सहगल, महासचिव नीरेन घोष व सह महासचिव कमल सरकार चुने गए. जी. के. राव, मुहम्मद इस्माइल, मुहम्मद अमीन, सुधीन कुमार, अमल घोष दस्तिदार व अजित सरकार उपाध्यक्ष बने तथा खिती बर्मन, गंगाधर रेड्डी, पीयूष नाग व दौलत राम सचिव बने. उपाध्यक्ष व सचिव का एक-एक पद खाली रखा गया है जिसे बाद में क्रमश: मध्यप्रदेश व उड़ीसा से भरा जाएगा.

चीन, जर्मन जनवादी गणतंत्र, यूगोस्लाविया, बंगलादेश, इंग्लैंड, आई. एल. ओ. तथा श्रीलंका की ट्रेड यूनियनों की ओर से सम्मेलन की बधाई संदेश मिले. सोवियत रूस की टैक्सटाइल एंड लाइट इंडस्ट्रीज वर्कर्ज यूनियन, जिसकी सदस्य संख्या 40 लाख है, ने अपनी केंद्रीय समिति की सचिव मारिया नैज्जगोदिना तथा नीना बोंदर को बिरादराना डेलिगेट के रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा.

सम्मेलन के अंत में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें 30 हजार से अधिक मजदूरों ने भाग लिया. इस सभा में लक्ष्मी सहगल, नीरेन घोष, मारिया नैज्जगोदिना तथा सम्मेलन के अतिथि व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भाषण दिये.

सीटू की बिहार कमेटी की बैठक

सीटू की बिहार राज्य समिति की बैठक 6 व 8 अक्तूबर को धनबाद जिले में कटरास नामक स्थान पर हुई. बैठक में सीटू केंद्र का प्रतिनिधित्व सीटू सचिव एम. के. पंधे ने किया.

समिति ने दिवंगत मजदूर नेताओं कामरेड दीनेन भट्टाचार्य व सुहृद मल्लिक चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

राज्य समिति के महासचिव चंडी प्रसाद ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर हुई बहस में 12 सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में हुए मजदूर संघर्षों का विवरण दिया.

एम. के. पंधे ने मुख्य उद्योगों के स्तर पर समन्वय समितियां बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कन्नानौर में हुई जनरल काउंसिल में लिए गए निर्णयों पर भी प्रकाश डाला.

समिति ने दो चरणों में ट्रेड यूनियन स्कूल चलाने का निश्चय किया. इस प्रकार का पहला स्कूल मधुपुर में 15 से 19 नवंबर तक चलेगा. समिति ने इस्पात, कोयला, बीड़ी जैसे बड़े उद्योगों में काम कर रही सीटू यूनियनों की समन्वय समितियां बनाने का भी निश्चय किया. इस निश्चय पर अमल करते हुए राज्य के इस्पात उद्योग की यूनियनों की बैठक एस. के. बक्शी आयोजित करेंगे व बीड़ी उद्योग में यह काम चंडी प्रसाद करेंगे. केंद्रीय सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों पर बनाई गई समिति में सीटू राज्य समिति के प्रतिनिधि सिराजुद्दीन अहमद होंगे.

समिति ने राज्य के बिजली मजदूरों की समस्याओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्णय किया. यह रिपोर्ट गणेशशंकर विधार्थी राज्य के मुख्य-मंत्री से इस संदर्भ में हुई अपनी बातचीत के आधार पर तैयार करेंगे. यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर मजदूरों में वितरित की जाएगी.

बैठक में पास किए गए एक प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि यूनियनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्री या श्रम सचिव से मिले. एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा यह मांग भी की गई है कि अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निधारण किया जाए.

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा गुआ में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की निंदा की गई है और मांग की गई है

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

सिंडीकेट बैंक कर्मचारियों का एकता व संघर्ष का आह्वान

सिंडीकेट बैंक स्टाफ यूनियन का दूसरा सम्मेलन पुणे में 3 से 6 अक्टूबर को संपन्न हुआ. सिंडीकेट बैंक स्टाफ यूनियन, अन्य बैंक कर्मचारियों व कई ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के लगभग 700 डेलीगेटों, पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया. यूनियन के अध्यक्ष वी. आर. कामथ ने अध्यक्षता की. स्वागत समिति के चेयरमैन के रूप में पुणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन के मेयर सुरेश तौर ने सम्मेलन का स्वागत किया.

सीटू के सचिव एम. के. पंधे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन के सदस्यों और इनके देश में मौजूदा स्थिति के साथ संबंध पर प्रकाश डाला. बैंक कर्मचारी फ्रंट पर बोलते हुए उन्होंने ए. आई. बी. ई. ए. की भूमिका की और इसकी गैर जनवादी कार्यों की आलोचना की. एम. के. पंधे ने सीटू की ओर से सम्मेलन को हार्दिक शुभकामाएं दी.

रिजर्व बैंक कर्मचारियों की ओर से आल इंडिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के सचिव डब्ल्यू. आर. वर्दाराजन ने सम्मेलन को बधाई दी. एन. सी. बी ई. के महासचिव ने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन को संबोधित किया. केनरा बैंक स्टाफ यूनितन और स्थानीय सीटू की ओर से क्रमशः जी. एम. वी. नायक और प्रभाकर माँकड़ ने सम्मेलन को बधाई दी.

यूनियन के महासचिव एम.एस.एन. राव ने अपनी रिपोर्ट पेश की. वेतन संशोधन आदि के लिए बैंक कर्मचारियों के संघर्ष की चर्चा करते हुए, राव ने कहा कि ए. आई. बी. ई. ए. जो अपने आपको 'सौदेबाजी' का एकमात्र ऐजेंट, समझती थी, ने बैंक कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया और इमर्जेंसी का समर्थन कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की. उन्होंने सिंडीकेट बैंक के प्रबंधकों की कोर्ट इंजंक्शन आदि की नीति की आलोचना की. उन्होंने घोषणा की कि सिंडीकेट बैंक स्टाफ यूनियन एक ऐसा संगठन है जो अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि देश के बेहूदा और जंगल कानूनों के खिलाफ भी लड़ेगा.

वी. आर. कामथ ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सिंडीकेट बैंक स्टाफ के सदस्यों का आह्वान किया कि वे अपने खोए अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें.

सम्मेलन ने मजदूर वर्ग, बैंक कर्मचारियों और आम जनता के फौरी मुद्दों पर कई प्रस्ताव अपनाए. सम्मेलन ने बैंक कर्मचारियों का आह्वान किया कि अपनी मांगों के लिए व सरकार की अधिनायकवादी तथा मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ एकता बनाएं व संघर्ष करें.

फरीदाबाद में शानदार रैली

17 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक रैली में 8000 से भी ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया. इस रैली को संयुक्त रूप से फरीदाबाद जिला सीटू कमेटी ने अन्य स्थानीय यूनियनों के साथ मिलकर पिछले वर्ष इसी दिन पुलिस व प्रबंधकों के गुंडों द्वारा मौत के घाट उतारे गए मजदूरों की याद में शहीद दिवस मनाने के लिए आयोजित किया था. 1979 में इसी दिन मजदूर राज्य सरकार व प्रबंधकों की मजदूर-वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली आयोजित कर रहे थे.

मजदूरों ने अपने 8 सूत्री मांग-पत्र को मंजूर करवाने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है. रैली को अन्यों सहित सीटू सचिव एम. के. पंधे ने संबोधित किया

इससे पहले, सीटू की फरीदाबाद जिला कमेटी ने मजदूर-वर्ग व आम लोगों के फौरी मुद्दों को हल कराने के लिए कई संघर्ष किए. 22 सितंबर को, किसानों की मांगों के समर्थन में बी. डी. ओ. के दफ्तर के सामने एक धरना दिया गया और बाद में बी. डी. ओ. को 8 सूत्री मांग-पत्र पेश किया गया. 23 सितंबर को खाद्य व आपूर्ति दफ्तर के बाहर एक धरना आयोजित किया गया और नियन्त्रक को 8सूत्री मांग-पत्र दिया गया जिसमें आवश्यक वस्तुओं का वितरण सस्ती दर पर उचित दर दुकानों से करने की मांग की गई थी. 24 सितंबर को एक दिन का धरना व बाद में रोजगार अधिकारी को 5 सूत्री मांग-पत्र दिया गया. 25 सितंबर को श्रम विभाग के बाहर एक दिन के धरने के बाद श्रम आयुक्त को एक 10 सूत्री मांग-पत्र पेश किया. 26 सितंबर को महिलाओं व कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक धरना आयोजित किया गया और उप-आयुक्त को एक मांग-पत्र दिया गया.

हिंदुस्तान कंप्यूटर्ज के कर्मचारियों का संघर्ष

हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंप्लाईज यूनियन सीटू ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन पर धरना देने का फैसला किया है. इस कंपनी की सावित्री कंप्लेक्स, नई दिल्ली, यूनिट की सभी कर्मचारी जिनमें 20 महिलाएं व एक पुरुष हैं, गैर कानूनी छटनी व तालाबंदी के खिलाफ संघर्षरत हैं. 29 जुलाई जिस दिन तालाबंदी हुई थी तब से ही ये कर्मचारी कंपलेक्स पर धरना दिये हुए हैं. यूनियन ने कई ट्रेड यूनियन कार्यवाहियां आयोजित की हैं और समझौता वार्ताओं का कोई फल नहीं निकला है.

तमिलनाडु सीटू का तीसरा सम्मेलन

सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति का तीसरा सम्मेलन 18-21 सितंबर को तिरुचेरापल्ली में हुआ. 230 यूनियनों (कुल सदस्य संख्या 1 लाख 21 हजार 639) का प्रतिनिधित्व करने वाले 387 डेलिगेटों ने सम्मेलन में भाग लिया. राज्य सीटू के पदाधिकारियों, बिरादराना डेलिगेटों व पर्यवेक्षकों को मिलाकर कुल डेलिगेटों की सदस्य संख्या 441 थी.

सम्मेलन के स्थान का नाम मजदूरों के महान नेता ए.के. गोपालन की याद में 'ए.के जी. नगर' रखा गया. सम्मेलन के सभा-भवन का नाम पोनमलाई (त्रिची) के 5 शहीद मजदूरों की याद में 'पोनमलाई थ्यागिकल अरंगम' रखा गया. याद रहे कि ये मजदूर सितंबर 1946 में रेलवे मजदूरों के ऐतिहासिक संघर्ष में अंग्रेज सरकार की गोलियों से शहीद हुए थे.

रेलवे मजदूर आंदोलन के एक नेता सुन्दरमूर्ति ने झंडे का अभिवादन किया. सम्मेलन का उद्घाटन ए. बालसुब्रमण्यम ने किया. ए. बालसुब्रमण्यम ने देश की एकता व अखंडता पर मंडराते साम्राज्यवादी बादलों की चर्चा की व बतलाया कि विश्व स्तर पर भी साम्राज्यवाद विश्व शांति के लिए खतरा बनकर उभर रहा है. उन्होंने देश के मजदूर वर्ग की जिम्मेदारियों व भावी कार्यक्रम का खाका प्रस्तुत किया.

अपने अध्यक्षीय भाषण में के. रमणी ने पिछले सम्मेलन के बाद के समय में राजनीतिक घटनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे अधिनायकवाद के उभरते खतरे का सामना करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाएं.

राज्य सीटू के महासचिव आर. उमानाथ ने रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट में बताया गया कि सीटू तमिलनाडु के मजदूर वर्ग में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुई है तथा यह कर्मचारियों व मजदूरों के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षिक कर रही है. सीटू ने राज्य में हो रहे मजदूरों के सभी संघर्षों में प्रमुख हिस्सा लिया है. सीटू द्वारा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करने तथा मजदूरों के विभिन्न वर्गों की मांगों के हक में उद्योग-स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के कारण राज्य में सीटू की साख बहुत बढ़ी है. सीटू की राज्य समिति सितंबर 1979 से तमिल भाषा में 'सीटू सेथी' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर रही है. इस पत्रिका का वितरण इस थोड़े समय में ही 2 हजार से बढ़कर 5 हजार हो गया है.

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में 42 डेलिगेटों ने भाग लिया. सम्मेलन में मेहनतकश लोगों की विभिन्न समस्याओं पर कई प्रस्ताव पास किए गए.

सीटू केंद्र की ओर से सम्मेलन को मुबारकबाद देते हुए समर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की वाम-मोर्चा सरकारों द्वारा मजदूर वर्ग के समर्थन में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की. सम्मेलन की शुभ कामनाएं देने वाले अन्य व्यक्तियों में प्रमुख थे— आर. रामराज (किसानसभा), एन. नामरामन (एस. वाई. एफ.), एम. बालाजी (एस. एफ. आई), के. श्रीनिवासन (इंशोरेंस एम्पलाईज एसोसियेशंज), पापा उमानाथ (डैमोक्रेटिक वीमैंज फेडरेशन) तथा विमला राव (वर्किंग वीमैंज कोआर्डिनेशन कमेटी).

सम्मेलन में 41 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति का चयन हुआ. इसके अध्यक्ष के. रमणी व महासचिव आर. उमानाथ निर्वाचित हुए.

21 सितंबर को सम्मेलन के समापन के अवसर पर एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसको समर मुखर्जी, ए. बालसुब्रमण्यम, के. रमणी, वी. पी. चिंतन, आर. उमानाथ तथा के. आनंद नंबियार ने संबोधित किया.

बिहार सीटू.....

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

कि मारे गए अथवा घायल मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए. बैठक ने इस गोलीकांड की सही जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को गुआ भेजने का निश्चय भी किया गया है. समिति ने मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी, ई. एस. आई,, ठेका मजदूरों आदि पर बनाई गई सरकारी समितियों में सीटू को सही प्रतिनिधित्व दिया जाए.

समिति ने निश्चय किया कि महंगाई, बेरोजगारी तथा काले अध्यादेश जैसे मुद्दों पर अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए व उसके अनुरूप राज्यव्यापी आंदोलन तैयार करना चाहिए. इसने स्थानीय नगर निगम कर्मचारियों के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन दिया. समिति ने निश्चय किया कि अगली बैठक में जनजातियों की मांगों पर विचार किया जाएगा. बैठक में हातिया मजदूर यूनियन की सदस्य संख्या रिपोर्ट को अंतिम रूप देने व जनवरी में चुनाव कराने का निश्चय भी किया गया.

राज्य के छोटे उद्योग धंधों पर विजयकांत लाल दास रिपोर्ट तैयार करेंगे जिस पर राज्य समिति की अगली बैठक में बहस होगी.

मुहम्मद इस्माइल ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करवाने में अपना पूरा सहयोग दें व इस संदर्भ में हुई प्रगति की राज्य समिति की अगली बैठक में समीक्षा करें. यह बैठक जनवरी 1981 में होनी निश्चित हुई है.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

रेल मजदूरों का बढ़ता संघर्ष

अधिकारियों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रेल मजदूर पिछले दो महीने से संघर्षरत हैं.

एक सितंबर को भिलाई लोको शेड के अधिकारियों द्वारा पदोन्नति-नियम का उल्लंघन करते हुए अपने दस चमचों की नियुक्ति करने के विरोध में मजदूरों ने अपना काम बंद कर दिया. अधिकारियों ने 3 सितंबर को मजदूरों को काम करने से मना कर दिया. संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ओ. एच. ई. कर्मचारी भी संघर्ष में उतर आये और लोको शेड मजदूरों ने गेट के बाहर तंबू खड़ा कर संघर्ष चालू रखा. अधिकारियों ने संघर्षरत नेताओं पर हमला करने व धमकाने के झूठे इल्जाम लगाए और बिना किसी कानूनी जांच के 11 नेताओं को आवश्यक सेवा रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करवा दिया गया. मजदूरों में भय पैदा करने के लिए पुलिस ने रेलवे कालोनी में मकानों की छान-बीन करनी शुरू की व नेताओं की पत्नियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. इस पर रेलवे कालोनी की 500 से भी ज्यादा महिलाओं ने डी. एस. पी. के खिलाफ एक जबर्दस्त प्रदर्शन किया जिसने बाद में छान-बीन को ही नहीं बंद करवाया बल्कि गिरफ्तार किए गए मजदूरों को भी रिहा कराया, हांलाकि संघर्ष अभी जारी था. 10 सितंबर को बिलासपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर के सामने भारी प्रदर्शन हुआ जिसने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत से मना कर दिया. एल. आर. एस. ए. ने भी बिरादराना संघर्ष के लिए 11 सितंबर से नियमानुसार-काम आंदोलन शुरू किया था. रेल मजदूरों की क्षेत्रीय कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक एम. एन. प्रसाद द्वारा बातचीत के लिए मध्यस्थता करने से 13 सितंबर को संघर्ष समाप्त हुआ.

एन. एफ. आई. आर. यूनियन के समाज विरोधी तत्वों ने आर. पी. एफ. अधिकारी के समर्थन से ड्यूटी को गये रेल कर्मचारी के घर को जबरदस्ती खोला व उसकी पत्नी के साथ बुरा सलूक किया लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने से 21 सितंबर को दंगोपोसी, एस. ई. रेलवे के सभी मजदूरों ने काम रोक दिया. दूसरी ओर अपने पद का फायदा उठाते हुए आर. पी. एफ. अधिकारी ने संघर्ष का नेतृत्व करने वाले 9 मजदूरों को गिरफ्तार करवा दिया. 400 महिलाओं ने पुलिस जीप रोककर अपनी कालोनी की महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने वाले नेताओं को परेशान किए जाने की बात पुलिस को सुनाई. महिलाओं द्वारा विरोध करने से पुलिस को मजबूर होकर गिरफ्तार मजदूरों को छोड़ना पड़ा. अधिकारियों ने संघर्षरत मजदूरों के साथ बातचीत करने से पहले तो इंकार किया लेकिन एम. एन. प्रसाद द्वारा जनरल मैनेजर के साथ समझौते के लिए मध्यस्थता करने से संघर्ष वापस लिया गया.

एन. ई. रेलवे का लोको रनिंग स्टाफ ने 4 महीने पहले कटिहार में हुए समझौते को न लागू करने व जुलाई में रेलवे बोर्ड द्वारा समरेश सोम को काम पर वापस लेने के आदेश को न मानने से एक अक्तूबर को नियमानुसार काम आंदोलन शुरू किया. 3 दिन लगातार आंदोलन के बाद अधिकारियों ने समझौता लागू कराने व सोम को वापस नौकरी पर लेने के आदेश जारी किए जिसके फलस्वरुप आंदोलन समाप्त हुआ.

रेलवे बोर्ड द्वारा 10 अक्तूबर तक बोनस का भुगतान करने के आदेशों का उल्लंघन करने से, 13 अक्तूबर को गोहाटी स्टेशन यार्ड पर लगभग 10 घंटे तक गाड़ियों का चक्का जाम रहा. अधिकारियों ने लोको शेड, कैरेज व शंटिंग स्टाफ को 10 अक्तूबर तक भुगतान नही किया. 11 अक्तूबर को मजदूरों ने 48 घंटे के अंदर भुगतान करने की अंतिम चेतावनी दी लेकिन अधिकारियों ने इसे अनदेखा कर दिया और काम बंद कर दिया गया. अधिकारियों द्वारा भुगतान करने पर मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है.

सी. सी. आर. यू. के नेतृत्व में मजदूरों ने 29 सितंबर को दक्षिण रेलवे के जरनल मैनेजर के सामने अपनी मांगों के समर्थन में एक प्रदर्शन किया और एक मांगपत्र भी दिया.

लोको रनिंग स्टाफ ने 4 अक्तूबर को देश भर में विक्टिमाइजेशन के खिलाफ जनरल मैनेजर के सामने प्रदर्शन किए. अब तक के समाचारों के अनुसार पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी व उत्तर-पूर्वी फ्रांटियर रेलवे द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन किए गए हैं.

मीटिंग और कानफ्रेंस

आल इंड़िया लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन की वार्षिक बैठक 22 और 23 सितंबर को दिल्ली में हुई जिसमें दो हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में, सतीश बहादुर को अध्यक्ष, पी. एन. नंदी को कार्यवाहक अध्यक्ष और श्याम बिहारी लाल को महासचिव चुना गया. यूनिफार्म की मांग पर प्रकाश डालने के लिए मजदूरों ने देश की राजधानी में बिना कमीज पहने प्रदर्शन किया.

दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन की मद्रास डिविजनल कानफ्रेंस 27 सितंबर को मद्रास में केरल समागम हाल में हुई जिसमें अन्यों सहित डी आर ई यू के अध्यक्ष के. आनंन नम्बीयार तथा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने भाग लिया.

सीटू का नवीनतम प्रकाशन

खदानों में कामगार महिलाओं की दशा

कीमत : 70 पैसे

मिलने का पता :

सी. आई. टी. यू. कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड़,
नई दिल्ली-110001

आसनसोल के कोयला मजदूरों द्वारा प्रदर्शन

आसनसोल क्षेत्र के लगभग 30 हजार कोयला मजदूरों ने कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया (सीटू) के नेतृत्व में अपनी 35 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन किया व मुख्य अधिकारी को एक मांग-पत्र पेश किया. हजारों की तादाद में स्त्री व पुरुष मजदूर रानीगंज, आसनसोल, भुगमा व अन्य क्षेत्रों से ट्रकों में व जुलूस के रूप में ई. सी. एल. स्टेडियम आए जहां एक रैली आयोजित की गई जिसके बाद ये मजदूर एक जुलूस बनाकर ई. सी. एल. दफ्तर पर गए.

कोयला मजदूरों की मांगों में सेकिंड नेशनल कोल वेज अवार्ड को लागू करवाना, आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर दुकानों पर करना, सुरक्षा उपायों को लागू करना, अस्पताल की अन्य सुविधाएं देना, आदि शामिल हैं.

कोलियरी मजदूर सभा के अध्यक्ष रोबिन सेन ने मजदूरों की ओर से मांग-पत्र पेश किया. इससे पहले एक मीटिंग आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता रोबिन सेन ने की और हाराधन राय, विजय पाल, बामापद मुखर्जी, संतोष दत्त व डी. एन. सिंह ने इस मीटिंग को संबोधित किया. इस मीटिंग में यह तय किया गया था कि यदि मजदूरों की मांगें एक महीने के अंदर पूरी नहीं की गईं तो कोयला मजदूरों को मजबूरन एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ेगी.

ए. डी. सी. ओ. के मजदूरों की जीत

सात महीने तक लगातार हड़ताल करने के बाद व इस दौरान कई कठिनाइयों का मुकाबला करके हुगली जिला की फैक्ट्री एडको लिमिटेड के मजदूरों ने प्रबंधकों को 5 अक्टूबर को एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया जो उनकी एक शानदार विजय रही. समझौते के अनुसार सभी छटनी हुए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लिया जाएगा, तदर्थ वृद्धि की अदायगी की जाएगी, अस्थाई व ठेके के मजदूरों को स्थाई काम दिया जाएगा, सभी चार्ज-शीटों को रद्द कर दिया जायगा, इसके अलावा अन्य मांगें भी स्वीकारी गई हैं. यह फैक्ट्री 24 अक्टूबर को फिर से चालू की जाएगी. इस संघर्ष का नेतृत्व एडको लिमिटेड कर्मचारी यूनियन ने किया था.

सिनेमा कर्मचारियों की लगातार हड़ताल

बंगाल मोशन पिक्चर एंप्लाईज यूनियन के नेतृत्व में राज्य के 10 हजार सिनेमा कर्मचारी 11 सितंबर से अधिक वेतन व बोनस आदि मांगों के लिए हड़ताल पर हैं. इसके तुरंत बाद ही सिनेमा मालिकान ने तालाबदी घोषित कर दी थी. ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के अड़ियल रवैये के कारण हाल ही में समझौते के लिए की गई त्रिपक्षीय बातचीत असफल रही. 15 अक्टूबर को त्यौहारों के कारण एक समझौता किया गया है जिसमें 16 अक्टूबर से ही हड़ताल व तालाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया लेकिन अंतिम समझौते के लिए आगे की बातचीत बाद में की जाने का निर्णय हुआ है.

चाय मजदूरों द्वारा बोनस-बहिष्कार जारी

चाय बागान मजदूरों की बोनस के प्रश्न पर चल रही त्रिपक्षीय बातचीत मालिकान के अड़ियल रवैये के कारण विफल रही. उन्होंने न्यूनतम 8.33 प्रतिशत निर्धारित बोनस के बदले मजदूरों की 20 प्रतिशत बोनस की मांग को नामंजूर कर दिया जिससे मजदूरों ने 8.33 प्रतिशन भुगतान का बहिष्कार कर दिया. राज्य में 263 चाय बागानों में से 16 बागानों के मालिकान 20 प्रतिशत देने के लिए राजी हो गए हैं और 33 और बागानों के मालिकान 8.33 प्रतिशत से ज्यादा देने के लिए तैयार हैं. यह बोनस-मसला अन्य 240 बागानों से संबंधित है. त्रिपक्षीय वार्ता के विफल होने के तुरंत बाद सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि राज्य के जंगल व यातायात मंत्री व ट्रेड यूनियन नेता परिमल मित्रा के चेंबर में मिले और यह तय किया गया कि मजदूरों की 20 प्रतिशत बोनस की मांग मंजूर होने तक बोनस-बहिष्कार संघर्ष जारी रखा जाए.

मेटल बाक्स मजदूरों द्वारा अनिश्चित काल के लिए काम बंद

मेटल बाक्स कंपनी की कलकत्ता स्थित फैक्ट्री के 3500 से भी ज्यादा मजदूर व कर्मचारियों ने 23 सितंबर को दो घंटे तक काम-बंद रखा. इस कंपनी के खड़कपुर बियरिंग यूनिट के मजदूर व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए व प्रबंधकों के अधिनायकवादी रवैये के खिलाफ 11 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के समर्थन में यह काम-बंद संघर्ष किया गया. खड़कपुर यूनिट के मजदूर व कर्मचारियों की प्रमुख मांग हैं : सभी मजदूरों को दो महीने की पगार, सहायकों को अधिक वेतन, प्रशिक्षण लेने वाले व कैजुअल मजदूरों को स्थाई करना व उन्हें मेटल बाक्स के अन्य यूनिटों के अनुसार सुविधाएं देना. इस हड़ताल का नेतृत्व मेटल बाक्स वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने किया था. प्रबंधकों के समर्थन पर समाज विरोधी तत्वों ने स्थानीय सी पी आई व कांगेस (आई) के लोगों के दबाव में आकर मीटिंग में बैठे हुए कई हड़ताली मजदूरों पर आक्रमण किया जिससे कई घायल हुए जिसके विरोध में ही अनिश्चितकाल के लिए काम-बंद चलाया गया.

चटकल मजदूरों का 20 प्रतिशत बोनस के लिए संघर्ष

पश्चिम बंगाल की 63 में से 62 चटकल मिलों के सभी मजदूरों ने सीटू, इंटक, एटक, उटक, एच एम एस और बी एम एस सहित 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 10 अक्तूबर को एक पूर्ण सफल सांकेतिक हड़ताल की. मजदूरों ने 20 प्रतिशत बोनस व कच्चे चटकल की कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित करने की मांग के लिए यह सांकेतिक हड़ताल की थी. यूनियनों नार्थ जूट मिल जो कमजोर यूनिट होने के कारण सरकार द्वारा संचालित है के मजदूर इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए क्योंकि प्रबंधकों ने पहले ही उनकी अधिक बोनस की मांग स्वीकार कर ली थी.

पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूर, 20 प्रतिशत बोनस के लिए 1979 से संघर्षरत हैं. 21 सितंबर 1979 को उन्होंने प्रत्येक शिफ्ट में 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और 10 अक्तूबर को उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अपने-अपने प्रबधकों के पास जन प्रतिनिधित्व-मंडल भेजा था. 12 नवबंर 79 को फिर इन मांगों के लिए ही मजदूरों ने प्रत्येक शिफ्ट में दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी. लेकिन चटकल व्यापारियों ने यह मांग नामंजूर कर दी और केवल 8.33 प्रतिशत बोनस ही दिया. चटकल व्यापारियों को दो साल में हुए जबरदस्त मुनाफे को ध्यान में रखते हुए मजदूरों ने इस साल 1978-79 के लिए 11.67 प्रतिशत बोनस की बकाया राशि का भुगतान व 1979-80 के लिए 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है. आई जे एम ए द्वारा प्रोत्साहित होकर चटकल व्यापारियों ने बोनस देने में आनाकानी करके मजदूरों की मांग को नामंजूर कर दिया और बोनस अधिनियम के अनुसार अपनी मन मर्जी से 8.33 प्रतिशत बोनस घोषित कर दिया. मजदूरों ने एकजुट होकर 8.33 प्रतिशत बोनस के भुगतान का बहिष्कार करने का निश्चय किया है और 1978-79 और 1979-80 के लिए 20 प्रतिशत बोनस की मांग पूरी होने तक संघर्ष करने का निश्चय किया है.

राज्य के श्रममंत्री कृष्णपद घोष द्वारा मध्यस्थता करने पर इस मसले का शांतिपूर्वक समझौता करने के लिए एक त्रिपक्षीय बातचीत की गई लेकिन आई जे एम ए ने मजदूरों की मांगों को मानने से इंकार कर दिया. जब बातचीत के अंतिम दौर में भी कोई समझौता नहीं हो सका तब उद्योग में कार्यरत सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 10 अक्तूबर को सांकेतिक हड़ताल करने का संयुक्त आह्वान करने का निश्चय किया.

10 अक्तूबर को चटकल मजदूरों की आई जे एम ए के कलकत्ता स्थित आफिस के बाहर एक विशाल रैली हुई जिसकी अध्यक्षता बी सी एम यू के महासचिव कमल सरकार ने की. रैली में बोनस बहिष्कार संघर्ष को सफलता मिलने तक जारी रखने का व त्यौहारों के बाद 20 प्रतिशत बोनस, चटकल उद्योग का राष्ट्रीयकरण व कच्चे चटकल का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल करने आदि मांगों के लिए संघर्ष तेज करने का निश्चय किया है.

बैंक कर्मचारियों का आह्वान.....

[पृष्ठ तीन से आगे]

तथा—संगठन के क्षत्र में योजनाबद्ध तोड़फोड़ के जरिये, फूटपरस्त यूनियनें खड़ी करके, उनकी नीतियों को न माननेवाली यूनिटों के निष्कासन और उनकी एफिलिएशन खत्म करने आदि की क्षतिपूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करेगा.

18. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह सम्मेलन एक तैयारी कमेटी बनाने का भी फैसला करता है जो पश्चिम बंगालराज्य में तीन महीने के अंदर या इसके बाद यथा शीघ्र कानफ्रेंस बुलायेगी.

19. 28 सदस्यों की तैयारी कमेटी, जिसे अन्य सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, को यह भी अधिकार दिया जाता है कि वह फंड इकठ्ठा करे, संविधान का मसविदा तैयार करे, अस्थाई रूप से यूनियनों को एनरोल करे, डैलीगेशन का आधार तय करे, एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए दूसरे राज्यों के बैंक कर्मचारियों की यूनियनों, एसोसिएशनों, फेडरेशनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करे और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए.

अब जिल्द में उपलब्ध हैं

सीटू मजदूर, 1979

कीमत : 10 रुपये

सीटू के सभी हिंदी प्रकाशन

कीमत : 5 रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय,
6, **तालकटोरा रोड,**
नई दिल्ली-110001

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

कोल इंडिया लि. के काम में मूल सुधार की सीटू द्वारा मांग

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में काम करने की दशा सुधारने के लिये पुनर्निरीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई फजल कमेटी के समक्ष सीटू ने सी आई एल में कुप्रबंध की घोर आलोचना की और कोयला खदानों में दशा सुधारने के लिए ठोस कदम लेने की मांग की है. वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष आर. बिल्लीमोरिया व अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित थे.

सीटू ने दीर्घकालीन द्विपक्षीय समझौते को लागू कराने के कई उदाहरण दिये. मजदूरों की जायज शिकायतों की ओर कठोर रवैया रखने से कोयला खदानों में औद्योगिक संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है. सरकार द्वारा कोयला खदानों में पर्याप्त बिजली की पूर्ति देने की असफलता से कोयले के उत्पादन पर गहरा प्रभाव हुआ है. कोयला, रेल, बिजली तथा इस्पात विभागों के मध्य कई सालों से चला आ रहा विवाद अब भी कायम है और इन विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है.

सीटू के अनुसार मजदूर तो उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन नौकरशाही लंबे समय से चली आ रही उनकी शिकायतें सुनने से इंकार करके उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर कर रही हैं. अधिकारियों व ठेकेदारों के गहरे संबंधों की जानकारी कई मौकों पर सरकार को ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई लेकिन सरकार इस मसले पर कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रही. कोयला खदानों की दशा सुधारने के लिए मजदूरों द्वारा दिए गये सुझावों पर विचार नहीं किया जाता.

सीटू ने मांग की कि कोयला उद्योग में संयुक्त परामर्श तभी माने रखता है. जब कोयला खदानों की दशा में भारी सुधार लाए जाएं. कोयला विभाग द्वारा किये जाने वाले काम असंतोषजनक हैं और मंत्रालय अधिकारी भी मजदूरों की शिकायतों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते है.

सीटू की ओर से, एम. के. पंधे, सचिव ने कमेटी में भाग लिया.

इस्पात मजदूरों का दूसरा सम्मेलन

बोकारो स्टील मजदूर यूनियन की दूसरी कानफ्रेंस 5 व 6 अक्तूबर को संपन्न हुई. इसकी अध्यक्षता यूनियन के बहिर्गामी अध्यक्ष हरे कृष्ण ने की. सीटू सचिव एम. के. पंधे ने कानफ्रेंस का उद्घाटन किया.

यूनियन के बहिर्गामी महासचिव जी.के. बक्शी ने यूनियन की स्थापना के बाद के कार्यों की रिपोर्ट पेश की. कई मजदूरों ने रिपोर्ट पर भाषण दिये व अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन करते हुए रिपोर्ट में सुधार करने का सुझाव दिया. कानफ्रेंस में मजदूरों की समस्याओं पर कई प्रस्ताव अपनाएं गए. अन्य कई स्टील प्लांट से बिरादराना प्रतिनिधियों ने कानफ्रेंस का अभिनंदन किया.

कानफ्रेंस ने एक वर्किंग कमेटी चुनी. सांसद मुहम्मद इस्माइल इसके अध्यक्ष चुने गए.

6 अक्तूबर को एक शानदार जनसभा आयोजित की गई जिसे अन्यों सहित जी. एस. विद्यार्थी, एम. के. पंधे, चंडी प्रसाद, मुहम्मद इस्माइल, हरे कृष्ण व जीवन बिहारी राय ने संबोधित किया.

20 नवंबर को इस्पात ठेका मजदूरों का मांग दिवस

अखिल भारतीय इस्पात मजदूरों की समन्वय समिति की बैठक 6 अक्तूबर को बोकारों में हुई जिसमें 12 अगस्त को हुए अखिल भारतीय विरोध दिवस की समीक्षा की गई. प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह विरोध दिवस सभी जगहों पर सफल रहा. इस्पात मजदूरों में हिंदी और बंगाली में लगभग 15 हजार किताबें बेची गई.

बैठक में ठेका मजदूरों की मांगों पर एक मांगपत्र एस. ए. आई. एल. के चेयरमैन को पेश करने का निश्चय किया गया. इन मजदूरों की शिकायतों को रोशनी में लाने के लिए एक किताब निकाली जाएगी जो देश के सभी ठेका मजदूरों में बेची जाएगी.

बैठक में, बाद में, 20 नवम्बर को अखिल भारतीय ठेका मजदूर दिवस मनाने का निश्चय किया है जिससे इस्पात उद्योग के ठेका मजदूरों की मांग को लोकप्रिय बनाया जा सके और इन मांगों के लिए अखिल भारतीय आंदोलन करने का निश्चय किया है.

चोर की दाढ़ी में तिनका

(28 अक्तूबर को नई दिल्ली में सांसदों की कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में श्रम राज्यमंत्री के भाषण के कुछ अंश हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं. ये अंश खुद बोलते हैं—सं०)

इस देश में जिन हालात में मजदूर काम करते हैं उनमें काफी सुधार होना चाहिए, हालांकि ये हालात एक उद्योग से दूसरे उद्योग में फर्क हैं. आमतौर पर वेतन स्तर बहुत कम हैं, इस स्तर पर भी मुद्रास्फीति के हालात में वास्तविक वेतन कम हो जाते हैं. कृषि, निर्माण उद्योग और अन्य रोजगारों में जहां काम की शर्तों का अभी नियमन नही हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में कामगार हैं और वे असुरक्षित महसूस करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य शर्तों के स्तर को तय करते हुए कई कनवेंशनें अपनायी है. हालांकि हमने इन कनवेंशनों को सिद्धांत रूप में माना है लेकिन उनमें से हम अनेक को अपना नही पाए हैं क्योंकि हमें इन स्तरों की प्राप्ति के लिए काफी रास्ता तय करना है.

आई सी आई कर्मचारियों का सम्मेलन

फेडरेशन आफ. आइ. सी. आई. एंड एसोसियेटिड कंपनीज एम्पलाईज यूनियंज का 27वां वार्षिक सम्मेलन 29-30 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ. फेडरेशन के अध्यक्ष एम. जी. नायक ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. महासचिव एस. बी. चटर्जी ने फेडरेशन की गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की.

सम्मेलन की उद्घाटन सभा में अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त सीटू कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी व सचिव एम. के पंधे ने भी भाषण दिए.

फेडरेशन ने कर्मचारियों के लिए पैंशन, ग्रैच्युटी व पी एफ. हासिल करने व सभी केंद्रों पर समान सेवाशर्तों को लागू करने में सफलता पाई है. इस समय फेडरेशन कम्प्यूटराइजेशन को समाप्त करने व सभी 7,500 कर्मचारियों के लिए समान दरों पर बोनस मिलने के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है.

चाय बागान मजदूरों पर गोली

असम के गोलपाड़ा जिले में कृष्णकली चाय बागान के मजदूर पिछले कुछ समय से 20 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे हैं. किंतु मैनेजर ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर कोई उचित समझौता निकालने के बजाय मजदूरों पर 8.33 प्रतिशत बोनस ही थोपना चाहा.

मजदूरों को आतंकित कर उन्हें कम बोनस लेने को मजबूर करने के इरादे से मैनेजर 12 अक्तूबर की रात को हाथ में बंदूक उठाए मजदूरों की बस्ती में गया तथा एक मजदूर को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया. इस हमले के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए मजदूर मैनेजर के घर के बाहर एकत्र हुए. पुलिस का एक दस्ता वहां पहले से ही मौजूद था. पुलिस ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप एक पुरुष व एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए.

सीटू की असम राज्य शाखा ने इस निर्दय गोलीकांड की तीखी भर्त्सना की है. इसने यह मांग की है कि मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाए व इस घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच हो.

संक्षिप्त समाचार

उड़ीसा सेल्ज रेप का विरोध : उड़ीसा सेल्ज रेप्रेजेन्टेटिव्ज यूनियन ने 29 अगस्त को कटक में ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का उद्देश्य ग्लैक्सो तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं व अन्य मजदूरों की छंटनी तथा इन कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे राष्ट्र विरोधी रवैये का विरोध करना था.

एकता दिवस का संयोजन : सीटू की उन्नाव (उत्तर प्रदेश) जिला कमेटी ने अन्य कई बिरादराना संगठनों के साथ मिलकर 15 अगस्त को उन्नाव में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया. इस अवसर पर हुई जन सभा में सीटू सचिव व संसद सदस्य नीरेन घोष ने भाषण दिया. इस क्षेत्र में गंगा घाट औद्योगिक परियोजना के विकास के साथ-साथ मजदूरों के आर्थिक हालात अच्छे होने के बजाय बदतर होते जा रहे हैं. मजदूरों की मांगों के लिए संघर्ष करते हुए सीटू ने इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है.

एयरलाइंज कैंटीन मजदूर : देश भर में इंडियन एयरलाइंज की कैंटीनों में काम करने वाले 500 से अधिक मजदूरों ने जल्दी ही सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया है. उनकी एक ही मांग है कि उन्हें एयरलाइंज के स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता मिले.

चीनी मजदूरों का प्रदर्शन : मेरठ (उत्तर प्रदेश) की रमाला चीनी मिल मजदूर यूनियन (सीटू) ने 18 अगस्त को फैक्ट्री गेट के सामने अपनी मांगों के समर्थन में विशाल प्रदर्शन किया.

लघु उद्योग मजदूर सम्मेलन : जयपुर स्माल स्केल कारखाना लेबर यूनियन (सीटू) का वार्षिक सम्मेलन 3 अगस्त को जयपुर में हुआ. इसका उद्घाटन सीटू की राजस्थान राज्य समिति के अध्यक्ष मोहन पुनमिया ने किया. मजदूरों के 80 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया.

ट्रेड यूनियन सम्मेलन : कई जनवादी संगठनों ने ससराम (बिहार) में सामूहिक रूप से 24 अगस्त को एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित किया. इन संगठनों में डालमिया वर्कर्ज यूनियन, किसान सभा, डी. वाई. एफ. तथा सीटू प्रमुख थे. सम्मेलन में मूल्य-वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राष्ट्रविरोधी हरकतों आदि अनेक मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए.

कोयला मजदूरों द्वारा प्रदर्शन : कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया की सी. सी. एल क्षेत्रीय कमेटी के आह्वान पर बरकाकाना क्षेत्र के मजदूरों ने 19 से 25 सितंबर तक बोनस मांग सप्ताह मनाया. 29 सितंबर को बिहार सी एम-एस आई के महासचिव आर. पी. सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने जनरल मैनेजर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया.

कोयला मजदूर गिरफ्तार : पुलिस व मालिकान की मिलीभगत पर 24 सितंबर को हजारीबाग में सांडी क्षेत्र में बिहार सी एम एस आई के महासचिव सहित 88 कोयला नेता व मजदूर गिरफ्तार किए गए. कांटीनेंटल कोक एंड मिनरल्ज के मजदूर आठ मजदूरों की छटनी के खिलाफ व आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन के लिए, फैक्ट्री नियम लागू करवाने आदि मांगों के लिए संघर्षरत थे.

दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष : फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन आफ इंडिया की 6 से 8 सितंबर को त्रिवेंद्रम में हुई 12वीं जनरल काउंसिल की मीटिंग में सारे देश से 262 प्रतिनिधियों व 57 प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया. इसमें सदस्यों व मजदूरों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा

मजदूरों पर किए जाने वाले शोषण के खात्मे व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया है. सीटू सचिव ई. बालानंदन ने 6 सितंबर को अधिवेशन को संबोधित किया व आम सभा को अन्यों सहित केरल के मुख्यमंत्री ई. के. नायनार ने संबोधित किया.

महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन : भिलाई स्टील प्लांट के मजदूरों ने बढ़ती महंगाई व सांप्रदायिकता के विरुद्ध 29 सितंबर को भिलाई में जुलूस निकाला. रैली मैदान जाते समय जुलूस को तितर-बितर करने के उद्देश्य से इंटक के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में कुछ गुंडों ने जुलूस पर आक्रमण किया जिसमें अन्यों सहित पी. के मुखर्जी घायल हुए. बाद में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई जिससे रैली ठीक समय पर आयोजित हो सकी.

पुलिस दमन के खिलाफ दिल्ली सी आई टी यू का सम्मेलन : दिल्ली सीटू कमेटी ने 31 अगस्त को कमला नगर में पुलिस दमन के खात्मे, 500 रु० प्रतिमाह न्यूनतम वेतन, आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में कर और आवश्तक वस्तुओं का वितरण सस्ती दरों पर उचित दर दुकानों के जरिये करने आदि की मांगों को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया. सम्मेलन शादीराम की अध्यक्षता में सपन्न हुआ जिसमें 10 महिलाओं समेत 350 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसी प्रकार का गाजियाबाद सीटू का सम्मेलन 30 अगस्त को भगवानदास की अध्यक्षता में हुआ. इसमें 5 महिलाओं सहित 280 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

संघर्षरत मजदूरों पर पुलिस दमन : हरियाणा ग्लास सेवाली के मजदूर 10 अक्तूबर से अपनी मांगों के समर्थन में संघर्षरत हैं. 15 अक्तूबर को पुलिस ने 15 कार्यकर्ता व मजदूरों को गिरफ्तार करके उन्हें राई पुलिस स्टेशन में निर्दयता से पीटा और बाद में उन्हें अपने स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर छोड़ दिया गया. इतना ही नहीं संघर्षरत मजदूरों के तम्बू, यूनियन बोर्ड तथा झंडे भी हटा दिए गए. पुलिस द्वारा मजदूरों की कालोनी में आंतक का वातावरण भी फैलाया गया था. पुलिस के इस कदम के बाद मजदूरों ने एक शानदार प्रदर्शन किया और जिला सोनीपत के उप-आयुक्त को एक मांग-पत्र पेश किया जिसमें गिरफ्तार किए गये मजदूरों की रिहाई की मांग शामिल है. सी आई टी यू के झंडे तले 700 से भी ज्यादा मजदूर लामबंद हैं.

सोनीपत में शानदार प्रदर्शन : दो हजार से भी ज्यादा मजदूरों ने एटलस फैक्ट्री गेट पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 30 अगस्त को एक शानदार प्रदर्शन किया जिसे अन्यों सहित हरियाणा सीटू के अध्यक्ष रघुबीर सिंह हूडा ने संबोधित किया था.

सीटू द्वारा श्रमिक शिक्षा शिविरों का आयोजन

सीटू ने अक्टूबर में मजदूरों की शिक्षा के लिए दो आवासी शिवर आयोजित किए. पहला शिविर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के निकट अध्यात्मिक नगर इंटर कालेज में 11 से 15 अक्टूबर को लगाया गया. इसमें 40 मजदूरों ने भाग लिया तथा मेजर जयपालसिंह, सुशील भट्टाचार्य, एम के पंधे व नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया.

दूसरा शिविर गुजरात में बड़ौदा के निकट चांडोड में आयोजित किया गया जिसमें 40 मजदूरों ने भाग लिया तथा वसंत राव महंदले, चंदू भाई पटेल, एम के पंधे व नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया.

इस शिक्षा कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन व वैज्ञानिक समाजवाद, विश्व के ट्रेड यूनियन आंदोलन व भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास, श्रम कानून, वेतन आदि जैसे विषयों पर शिक्षा दी गई. इस साल नवंबर व दिसंबर में विभिन्न राज्यों में कई और शिक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	जून	जुलाई.	अगस्त
बिहार			
जमशेदपुर	378	386	388
झारिया	360	368	374
कोडर्मा	410	412	421
मोंघाइर	410	422	440
नोआमुंडी	376	377	379
गुजरात			
अहमदाबाद	366	371	372
भाव नगर	391	399	409
हरियाणा			
यमुना नगर	423	436	430
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	404	409	405
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	406	419	429
भोपाल	385	393	396
ग्वालियर	415	425	425
इंदौर	396	409	416
महाराष्ट्र			
बंबई	389	399	396
नागपुर	382	392	393
शोलापुर	389	401	403
पंजाब			
अमृतसर	394	408	416
राजस्थान			
अजमेर	405	420	422
जयपुर	425	433	438
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	381	389	398
सहारनपुर	394	401	405
वाराणसी	442	446	457
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	391	395	402
कलकत्ता	375	381	387
दार्जीलिंग	325	327	331
हावड़ा	359	363	370
जलपाइगुरी	323	331	339
रानीगंज	375	379	390
दिल्ली	412	423	428
भारत	386	394	397

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की संघर्ष की अगली तैयारी

केन्द्र सरकार कर्मचारी और मजदूर के फेडरेशन के आह्वान पर लाखों केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने 30 सितंबर को वेतन न लेने का निश्चय किया. उनका यह कदम बहुत सफल रहा. इस प्रकार एक दिन सांकेतिक तौर पर वेतन न लेकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया. यह कदम उन आम मांगों के लिए उठाया गया जो लगभग सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हैं. इसमें विशेष है बोनस की मांग.

कनफेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी विभिन्न राज्यों में कार्यरत समन्वय समितियों से 12 व 13 अक्तूबर को मिली तथा भविष्य के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करवाने के विषय पर चर्चा की. अफसोस की बात है कि अब तक बोनस के सवाल पर केन्द्र सरकार ने कनफेडरेशन के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत नहीं की है. कनफेडरेशन ने बोनस को स्थगित मजदूरी मानने के अपने सिद्धांत को दोहराया है और कहा है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस अवश्य ही दिया जाना चाहिए.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 15 नवम्बर तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का निश्चय किया है. यदि ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी की बैठक से पहले वित्त मंत्री की ओर से बातचीत का निमंत्रण नहीं आता तो 28 अक्तूबर को वित्त मंत्रालय के सामने धरने का आयोजन किया जाएगा. संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया जाएगा तथा ए.आई.आर.एफ. और ए.आई.डी.ई.एफ. के साथ मिलकर संयुक्त कदम उठाए जाएंगे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह भी निश्चय किया कि 28 अक्तूबर को अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में मनाया जाए तथा 20 नवम्बर को केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा देश भर में सभाएं व प्रदर्शन किए जाएं.

दिसम्बर के आरंभ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हालात की समीक्षा करेगी व बोनस जैसी समान समस्याओं पर ए.आई.आर.एफ., ए.आई.डी.ई.एफ तथा एन.एफ.पी.टी ई. के साथ मिलकर संयुक्त आंदोलन तैयार करने का प्रयत्न करेगी.

महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद

कांग्रेस (अर्स), सी पी आई (एम), सी पी आई, जनता, पी डब्ल्यू पी, लोकदल तथा आर. पी. आई. (जी.) के आह्वान पर तथा सीटू, एटक, उटक, एच एम एस तथा अन्य दफ्तर कर्मचारियों के संगठनों आदि यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति के समर्थन पर शहरी व देहाती क्षेत्रों के सभी मुख्य तबकों ने 15 अक्तूबर को महाराष्ट्र बंद आयोजित किया जो लगभग पूर्ण सफल रहा.

राज्य के मजदूर-वर्ग, भूमिहीन श्रमिकों छोटे किसानों, छोटे दुकानदारो मध्यमवर्गीय कर्मचारियों, महिलाओं, युवक तथा छात्रों आदि ने पूरे जोर के साथ इस बंद को कामयाब बनाया.

बंद महंगाई, महिलाओं व कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचारों, कानून और व्यवस्था के बिगड़ते हालात, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निवारक नजरबंदी अध्यादेश के विरोध में आयोजित किया था.

बंद को नाकामयाब बनाने के प्रयत्न में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगाकर पांच व्यक्ति एकत्र होने पर भी पाबंदी लगा दी थी. 5000 से भी ज्यादा लोग. गिरफ्तार किये गये जिनमें अहिल्या रांगणेकर. रामचंद्र घंघारे, बी. पी. कश्यप शामिल हैं.

धारा 144 के बाबजूद सारे राज्य में बंद को जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ. अनुमान है कि राज्य के 40 से 50 लाख मजदूरों तथा कर्मचारियों ने बंद में भाग लिया. इंटक से संबद्ध और सरकार व प्रबंधकों की कठपुतली राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के जबरदस्त विरोध के बाबजूद, टैक्सटाइल मिलों के 2 लाख मजदूरों ने बंद में हिस्सा लिया जो एक शानदार जीत रही. बंद को विफल करने के लिए किए गये जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त के बाबजूद अनेक स्थानों पर मीटिंग व रैलियां आयोजित की गई.

त्रिपुरा सहायता कोष

पश्चिम बंगाल राज्य समिति के कलकत्ता स्थित हाल में 27 सितंबर को राज्य सीटू के महासचिव मनोरंजन राय ने दौरे पर आए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपेण चक्रवर्ती को त्रिपुरा सहायता कोष के लिए 68 हजार रुपये का एक चेक भेंट किया. यह राशि सीटू की राज्य समिति के आह्वान पर 313 यूनियनों की ओर से दी गई. इससे पहले भी राज्य के मजदूर वर्ग ने इस कोष में धन दिया है. इस अवसर पर पंजाबी दैनिक 'नबी प्रभात' की ओर से 500 रु० का एक चैक भी मुख्यमंत्री को दिया गया.

इसी दिन एक अन्य सभा में राज्य सरकार कर्मचारी समन्वय समिति ने भी 2 लाख रुपये का चैक मुख्यमंत्री को दिया.

दोनों सभाओं में बोलते हुए नृपेण चक्रवर्ती ने कहा कि विभिन्न जातियों को एक-दूसरे के नजदीक लाने व एकजुट आंदोलन करने के हमारे प्रयत्नों का अच्छा नतीजा निकला है. इसके परिणामस्वरूप उपद्रवग्रस्त इलाकों में भी जनजातियों तथा बंगाली समुदाय के व्यक्ति पहले से भी अधिक प्रेम व सहयोग से रह रहे हैं.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित